मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक

वर्ष: 43 अंक: 35 नई दिल्ली (कुल पेज 16) 27 अगस्त – 2 सितंबर 2023 मूल्य 7 रुपये

अंदर के पेजों में

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम.....5

गुजरात में प्रगतिशील लेखन: एक विहंगावलोकन.....8–9

बहाल होगा गंगा का निर्मल अविरल बहाव?.....10

प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस संबोधन

भाजपा का राजनीतिक मंच नहीं है लाल किला

टी.एम. मूर्ति

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तमिलनाडु राज्य इकाई की राज्य परिषद की 14 से 17 अगस्त तक सलेम में बैठक हुई। राज्य परिषद ने केंद्र सरकार की भर्त्सना करते हुए कहा कि मोदी सरकार की नीतियां कारपोरेट परस्त और जनविरोधी हैं। इन नीतियों के कारण महंगाई दिन दूनी–रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। मोदी सरकार राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनने की कोशिश कर रही है, सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्तियों को बेचकर देश को तबाह कर रही है, कारपोरेट तबके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से लिए गए ऋणों को बट्टेखाते में डाल रही है, गैर–हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को थोप रही है और अपने सांप्रदायिक एजेंडे से देश के लोगों की एकता को नुकसान पहुंचा रही है। राज्य परिषद ने केंद्र सरकार की कारपोरेट परस्त और जनविरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए हर जिले, तालुका और औद्योगिक केंद्र में केंद्र सरकार के कार्यालयों पर पिकेटिंग करने का फैसला किया। पिकेटिंग का कार्यक्रम तीन दिन चलेगा।

राज्य परिषद की बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा और मर्यादा को ताक पर रख दिया। उन्होंने इसे भाजपा की एक चुनाव अभियान मीटिंग का रूप दे दिया। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के अपने सम्बोधन में विपक्षी पार्टियों पर हमला कर स्वतंत्रता दिवस की मर्यादा का उल्लंघन किया।

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा के शासन के नौ साल बाद आज पूरा देश अस्तव्यस्त है। 2014 में मोदी ने लोगों से वायदा किया था कि भाजपा की सरकार आ गई तो हर साल दो करोड़ नए रोजगार का सृजन किया जाएगा, भारतीयों के विदेशों में जमा काले धन को लाकर हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराए जाएंगे। उन वायदों का क्या हुआ?

मणिपुर में जारी अशांति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 3 मई से लगातार मणिपुर अशांत है, गृहयुद्ध जैसी स्थिति बन गई है, महिलाओं के साथ अकथनीय दुर्व्यवहार एवं हिंसा हो रही है। परंतु प्रधानमंत्री ने खामोशी ओढ़ रखी है। क्या वे समझते हैं कि उनके मौन धारण करने से मणिपुर की समस्या खत्म हो जाएगी? मणिपुर के हालात देखते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह ऐसा करने को तैयार नहीं। राजनीतिक फायदे के लिए वह जनता के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से लड़ाते रखना चाहते हैं।

डी. राजा ने कहा लोकसभा का अगला चुनाव नजदीक आ रहा है और प्रधानमंत्री का स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाषण एक चुनाव अभियान के अलावा कुछ न था। देश के संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए सभी धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और वामपंथी पार्टियां एकजुट हुई हैं और उन्होंने ''इंडिया'' गठबंधन (इंडियन नेशनल डवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायन्स–आईएनडीआईए (भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशी गठबंधन)) बनाया है।

विपक्ष की पार्टियां एकजुट हैं। ''इंडिया'' गठबंधन की पहली बैठक कर्नाटक के विधान सभा चुनावों के बाद पटना में आयोजित की गई। दूसरी बैठक बंगलौर में हुई। तीसरी बैठक 31 अगस्त से 1 सितंबर तक बंबई में आयोजित किए जाने का कार्यक्रम है।

यह प्रसन्नता की बात है कि इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों के बीच एक तालमेल बन रहा है। सभी पार्टियों को एकोमोडेट करने के लिए सर्वसम्मति बनाई जा रही है,सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करने के लिए रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। इंडिया गठबंधन की अब तक की मीटिंगों से उम्मीदें बढ़ी हैं। इस बात से प्रधानमंत्री मोदी डरे हुए हैं। संसद में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में भी उनका यह डर झलक कर सामने आया।

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में लफ्फाजी का सहारा लिया और खोखले वायदे किए। उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री बनने की आशा व्यक्त की। वह स्वयं ऐसा कैसे तय कर सकते हैं? यह तो जनता का काम है। इसके अलावा वह किसी चुनाव अभियान में तो बोल नहीं रहे थे, वह स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का सम्बोधन था। उसमें उन्हें भाजपा या आरएसएस के नेता के तौर पर नहीं बोलना चाहिए था। उन्हें प्रधानमंत्री के पद की गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए था। लंबे सम्बोधन के दौरान उन्होंने जो आंकड़े दिए वह फर्जी और मनगढ़त थे।

भाजपा को अपनी विफलताओं का डर है और वह हिंसा के जरिये देश में वातावरण को अशांत बनाना चाहते हैं। मणिपुर में तो हालात अत्यंत अशांत चल ही रहे हैं, ऐसे में उन्होंने हरियाणा में हिंसा क्यों पैदा की? वह अल्पसंख्यकों का सामाजिक बहिष्कार कर बहुसंख्यक हिन्दुओं के दिलोदिमाग में जहर भरना चाहते हैं।

डी. राजा ने आगे कहा कि उनकी नफरत की राजनीति इस हद तक चली गई है कि उन्होंने हिन्दुओं को उकसाने की कोशिश की कि मुस्लिम दुकानों से कुछ न खरीदें और मुस्लिम होटलों में खाना न खाएं। राजनीतिक फायदे के लिए मतदाताओं का धार्मिक ध्रुवीकरण करना भाजपा की सर्वविदित रणनीति रही है। देश के लोग उसकी कुटिल नीति को समझ चुके हैं। लोगों में सांप्रदायिक फूट डालने की यह नीति अब आगे कामयाब होने वाली नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि जो पार्टियां इंडिया गठबंधन में शामिल हैं उनमें अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार चुनने की परिपक्वता है। परंतु अब हमारा लक्ष्य भाजपा को सत्ता से हटाना है और तात्कालिक कर्तव्य है कि देश को बचाया जाए। नेता कौन होगा यह समस्या नहीं है। जब भाजपा को सत्ता से हटाकर एक वैकल्पिक सरकार बनाने का समय आयेगा तो हमारी टीम बैठक करेगी और फैसला लेगी।

एक प्रश्न के उत्तर में डी.राजा ने कहा कि प्रधानमंत्री दो करोड़ महिलाओं को लखपति महिला बनाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। महिलाएं इस पर विश्वास नहीं करेंगी। मोदी ने तो ''बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं'' का नारा भी दिया था। परंतु आज बेटियों का क्या हाल है? महिला पहलवानों के साथ जो नृशंसता हुई और मणिपुर की माँओं के साथ जो कुछ हुआ प्रधानमंत्री मोदी ने उसके संबंध में मुंह क्यों नहीं खोला?

डी. राजा ने आगे कहा कि संसद में भाजपा का बहुमत है। तो फिर संसद और विधान सभाओं में महिलाओं को समुचित आरक्षण देने के लिए बिल क्यों नहीं पारित किया गया? क्या प्रधानमंत्री महिलाओं को विधायिका में आरक्षण के बिल को पारित करने के लिए आगे बढ़ेंगे और महिलाओं को वाजिब आरक्षण प्रदान करेंगे?

भयानक लूट का सिलसिला

संपादकीय

आज जब देश की जनता बेरोज़गारी की कालिख से अंधेरी जिन्दगी की गलियों से गुजर रही है, भूख की तड़प में, फटे कपड़ों में, और टपकती झोपड़ियों में।

तो यह ख़बर सारे देश को झकझोर कर रख देती है कि आयुष्मान भारत की 7.5 लाख जनता आज एक ही मोबाईल नंबर पर रजिस्टर्ड है। सी.ए.जी. या कैग की रिपोर्ट पार्लियामेन्ट में पेश हो चुकी है जिसमें यह भी सूचना है कि 88, 670 मृत व्यक्तियों के नाम, फिर से चिकित्सा के विभिन्न इंश्योरेन्स की रकम दी जा चुकी है। यह सत्य कहीं भी सामने नहीं आया है कि अगर बीमार या जिन्हें मृत व्यक्तियों में रखा गया है, इस रकम से लाभाविन्त हुए हैं या कहीं और इसे दिया गया है।

वस्तुतः आयुष्मान भारत तक ही बात खत्म नहीं होती, द्वारका एक्सप्रेस वे सहित सात घोटालों को सी.ए.जी. ने सीधे संसद में पेश किया है। इन सबकी सफाई या इससे जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। वहां सिर्फ ख़ामोशी ही मिलती है। पैसा, जो आम आदमी का था, उनकी मेहनत की एवज में उन्हें मिला था, और इसमें से उन्होंने देश को टैक्स के रूप में दिया था राष्ट्र–निर्माण के लिये। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या पी.एम.जे. एक इंश्योरेन्स की स्कीम है। कम्पट्रोलर एन्ड ऑडिटर जेनरल ने उद्घाटित किया है कि 6. 97 करोड़ रुपयों का भुगतान 3,446 बीमारों के इलाज के लिये किया गया था। ये सभी बीमार कहीं नहीं हैं। इनके डाटाबेस के अनुसार, इन्हें मरे हुए लंबा समय बीत चुका है।

इस स्कीम की शुरुआत ही हुई 2018 में। यह गरीबों को और असहाय लोगों के राहत देने के लिये बनी थी और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में बसने वाले इन लोगों को बीमारी से मुक्त करने के लिये बनी थी। इनकी कार्यकुशलता के ऑडिट के समय ये सभी घोटाले सामने आने लगे। इसके शीर्षक से ही पता चल जाता है कि इसकी जड़ें आखिर कहां तक गहरी हैं। जिन्हें इंश्योरेन्स की रकम मिल रही थी, उन्हें पहले के इलाज के दौरान ही मृत घोषित कर दिया गया था।

सी.ए.जी. ने ऐसे रोगियों का पता लगाया जिन्हें ट्रान्जेक्शन मैनेजमेंट सेक्शन ऑफ स्कीम या टी.एम.एस ने मृत घोषित किया था, और फिर भी उनकी चिकित्सा चालू थी। ऑडिट में यह स्पष्ट हुआ कि इंश्योरेन्स की रकम के लिये ऐसी कम से कम 3,903 मांगे आई थीं। मध्यप्रदेश का उदाहरण ले लें तो ऐसे 403 रोगियों को 2,60,09,723 रुपये इलाज़ के लिये मिले। इस स्कीम के निर्देशों में यह साफ लिखा है कि अगर रोगी की मृत्यु अस्पताल में एडमिशन होने के बाद होती है और वह भी वहां से डिस्चार्ज होने के पहले, तो अस्पताल से खर्चा ऑडिट के बाद ही दिया जा सकेगा। और यह हॉस्पिटल को ऑडिट के बाद दी जाएगी।

डेस्क ऑडिट जुलाई, 2020 में ऑडिट ने खुलासा नेशनल हेल्थ ऑथरिटी (एन.एच.ए.) को किया कि टी.एम.एस. के आई.टी. सिस्टम में उसी इलाज में जब कोई रोगी मृत घोषित होता है जिसमें पहले भी वह मृत ही था, उन्हें भुगतान किया जाता है। एन. एच.ए. ने ऑडिट की टिप्पणी को मान लिया, और इस पर सीएजीए ने कहा कि अप्रैल 22,2020, में सारी सावधानी को ध्यान में रखते हुए किसी रोगी को पी.एम.जे.आई.डी. में मृत घोषित किया जाता है तो वह स्कीम का लाभ नहीं उठा सकता। सी.ए.जी. की इस रिपोर्ट के अनुसार जब आवश्यक सावधानियों को ध्यान में नहीं रखा गया तो एन.एच.ए. ने अगस्त 2022 में कहा कि हॉस्पिटल में एडमिशन को पुरानी तारीख पर दिखाया जा सकता है, क्योंकि कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सी.ए.जी. ने इस कैफियत पर टिप्पणी करते हुए कहा, ''जवाब संतुष्ट नहीं करता और प्री ऑथराइजेशन की शुरुआत में, मांग को सबमिट करने और राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा मांग को स्वीकृत करने के पहले ही अगर ''लाभार्थी पहले के इलाज के सिलसिले में मृत घोषित हो चुका है तो इस मांगपत्र की याचिका में ही अशुद्धि है और इसके कार्यान्वयन में भविष्य में इसका लाभ उठाया जा सकता है।'' ए.बी. –पी.एम.जे. के डाटाबेस में गलत नाम, गलत जन्म की तिथि, नकली स्वास्थ्य पहचानपत्र और अवास्तविक परिवार सदस्यों की संख्या दर्ज है, यह सरकारी ऑडिटर की रिपोर्ट में दर्ज है जिसे पार्लियामेन्ट में पेश किया गया।

इस सारे विनाश की धारा में एक के बाद एक और घोटालों का सिलसिला बना ही हुआ है। सी.ए.जी. की रिपोर्ट के अनुसार स्वच्छ भारत पखवाड़े में उन्नीस राज्यों में पेंशन स्कीम में जमा पैसों का विज्ञापन के लिये खर्च किया गया।

वयस्क नागरिक, विधवा और अपंगों के लिये ग्रामीण विकास मंत्रालय में पेंशन के तहत जमा पैसों को भी नहीं छोड़ा गया। उसे भी किसी और स्कीम के विज्ञापन में खर्च कर दिया गया।

सरकारी ऑडिटर के इस महीने की शुरुआत में जारी रिपोर्ट में ''नेशनल हाई वे ऑथरिटी ऑफ इंडिया द्वारा टोल प्लाजा की दक्षिण भारत में सक्रियता'' के शीर्षक के साथ यह कहा गया है कि पांच टोल प्लाजा में उस सड़क के यात्रियों को 132.5 करोड़ रुपयों का अनावश्यक भार उठाना पड़ा। इस रिपोर्ट के लिये, सी.ए.जी. ने पांच दक्षिण भारतीय राज्यों में 41 टोल प्लाजा का ऑडिट किया था।

अन्य घोटालों में द्वारका एक्सप्रेस वे और अयोध्या डेवेलपमेन्ट प्रोजेक्ट पर लगे आरोप शामिल हैं, और साथ ही, भारतमाला परियोजना के दुरुपयोग का भी जिक्र है। केंद्र की सड़क विकास योजना, भारतमाला परियोजना और इसके निर्माण का खर्च 15.37 करोड़ प्रति किलोमीटर से 32 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गया है।

भारतमाला परियोजना के निर्माण के क्रम में फेज वन पर पिछले महीने सी.ए.जी. की रिपोर्ट आई है। इसमें टेन्डर के समय से ही भ्रष्टाचार शुरु हो गया है, प्रोजेक्ट की कोई विस्तृत रिपोर्ट भी अभी तक नहीं आयी है। एसक्रो एकाउन्ट्स से भी 3,500 करोड़ रु. की हेराफेरी हुई है। टूरिज्म के मंत्रालय में ''स्वदेश दर्शन स्कीम'' का प्रावधान है, जिसमें विरोधी पक्ष का दावा है कि वह भ्रष्टाचार से जर्जर हो चुका है। ''अयोध्या विकास परियोजना'' में सी.ए.जी. रिपोर्ट के अनुसार अनेक घोटाले दर्ज हैं।

ठेकेदारों को जो पैसे दिये गये, उन्हें रजिस्टर नहीं किया गया। जी.एस.टी. के पैसे भी उन्ही के खाते में जा रहे हैं। कौन हैं ये लोग? क्या कर रहे है? वे और टेन्डरिंग की विधि इतनी भ्रष्ट कैसे है?

सी.ए.जी. ने अपने ऑडिट की बुनियाद पर इन घोटालों का खुलासा पार्लियामेन्ट में किया है, यह मनमाना आरोप नहीं है, सत्य का प्रामाणिक उद्घाटन है।

एआईएसएफ का रहा है 87 वर्षों का गौरवशाली इतिहास

नई दिल्ली: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का 88वां स्थापना दिवस 12 अगस्त, 2023 को नई दिल्ली में संगठन के राष्ट्रीय मुख्यालय में मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन भाकपा दिल्ली राज्य परिषद के सचिव दिनेश वार्ष्णेय ने किया। इस अवसर पर एआईएसएफ महासचिव विक्की महेसरी भी मौजूद थे। अपने उद्घाटन भाषण में दिनेश वार्ष्णेय ने आजादी और संघर्ष में एआईएसएफ की महान ऐतिहासिक भूमिका की सराहना की। उन्होंने यह भी बताया कि कैसे एआईएसएफ ने सार्वजनिक शिक्षा को बचाने के संघर्ष को आगे बढ़ाया। संबोधन में एनईपी 2020 के खतरों के बारे में भी बताया गया। शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण और व्यावसायीकरण का पूरा एजेंडा है। उन्होंने एआईएसएफ के वर्तमान नेतृत्व से सार्वजनिक वित्त पोषित शिक्षा के निजीकरण के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखने की अपील की।

अपने उद्बोधन में विक्कसी महेसरी ने कहा कि एआईएसएफ सभी के लिए मुफ्त, अनिवार्य और वैज्ञानिक शिक्षा के लिए संघर्ष करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि एआईएसएफ छात्र हितों के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगा। स्थापना दिवस कार्यक्रम में दिल्ली, जामिया और जवाहरलाल विश्वविद्यालय के छात्रों ने भाग लिया।

दरभंगा, (बिहार)

ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन (एआईएसएफ) का 88वें स्थापना दिवस के अवसर पर कामरेड भोगेन्द्र झा नगर स्थित प्रधान कार्यालय में संगठन के राज्य सह सचिव शरद कुमार सिंह, जिला सचिव शशिरंजन और जिलाध्यक्ष अरशद सिद्दीकी ने संयुक्त रूप से झंडोतोलन किया। झंडोतोलन के उपरांत भगत सिंह अमर रहें सहित आजादी आन्दोलन के मनीषियों व संगठन के शहीद साथी अमर रहें के गंगनचुंबी नारे लगें। मौके पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संगठन के राज्य सह सचिव शरद कुमार सिंह ने कहा कि एआईएसएफ का 87 वर्षों का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। ऑल इंडिया स्टूडेंटस फेडरेशन की स्थापना 12–13 अगस्त को गंगा मेमोरियल हॉल लखनऊ में की गयी थी। संगठन की स्थापना भगत सिंह के क्रांतिकारी सहयोगी जो भगत सिंह के फांसी के उपरांत देशभर में हुए उग्र आजादी आंदोलन के दबाव में जिन्हें अंग्रेज

एआईएसएफ का स्थापना दिवस

सरकार ने जेल से रिहा कर दिया था। उन तमाम आजादी के मनीषियों के द्वारा की गयी थी। उस समय के स्थापना सम्मेलन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। वहीं संचालन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया, जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री हुए थे। इसके स्थापना काल के कई सदस्यों ने आजादी के आंदोलन में अपनी आहुति दी थी। उस समय में संगठन का स्थापना का उद्देश्य देश की आजादी में छात्र नौजवानों को एकजुट कर आजादी आन्दोलन को मजबूत करना था।

देश की आजादी के उपरांत भी संगठन की आवश्यकता लगी और लगातार संगठन 'राष्ट्रपति हो या चपरासी की संतान–सबको शिक्षा एक समान', 'समान स्कूल प्रणाली लागू करने' सहित सभी के लिए शिक्षा और रोजगार की मांग को लेकर संघर्ष कर रही है। संगठन के आंदोलन के दबाव में कई छात्र–नौजवान हित में कार्य हुए हैं। वहीं देश को सशक्त और शिक्षित बनाने के लिए संगठन ने अपनी महती भूमिका निभाई है। संगठन से जुड़े हुए कई लोगों ने अभी तक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री बनकर इस देश के विकास में अपनी महत्ती भूमिका निभाई है। संगठन लगातार छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी कार्य करता रहा है। वहीं संगठन के जिला सचिव शशिरंजन ने कहा कि संगठन के आंदोलन के कारण ही आज मिथिला विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है। मिथिला विश्वविद्यालय सहित कई महाविद्यालय संगठन के संघर्षों के बल पर बना है। संगठन के कारण ही समस्तीपुर से दरभंगा बड़ी रेलवे लाइन बनी। वहीं दरभंगा आकाशवाणी स्थापित हुई। संगठन लगातार शिक्षा रोजगार के बेहतरीन के लिए संघर्ष कर रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष अरशद सिद्दीकी ने कहा कि संगठन को पुराने दौर की तरह मजबूत कर छात्र को एकजुट कर संघर्ष करना होगा। इसके लिए गांव, पंचायत, अंचल, विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर नए सदस्यों की भर्ती कर इकाई गठन कर संघर्षों को तेज करना होगा। मौके पर जिला उपाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार साहु, जिला सह सचिव अखिलेश कुमार, कोषाध्यक्ष निखिल कुमार, शंकर यादव, रौशन कुमार, रवि कुमार सिंह, सतीश कुमार, मुन्ना कुमार, विकास कुमार, रौशन कुमार पंडित, प्रशांत कुमार, आदित्य मंटू, राहुल कुमार, रविरंजन प्रसाद, आदित्य पाण्डेय, सुधीर कुमार आदि ने संबोधित किया।

भाकपा प्रतिनिधिमंडल का हिंसा से तबाह मणिपुर का दौरा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा के नेतृत्व में एक भाकपा प्रतिनिधिमंडल ने हिंसा से तबाह मणिपुर का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्य थे पार्टी के राष्ट्रीय सचिवगण–बिनोय विश्वम संसद सदस्य, डॉ. के. नारायणा एवं रामकृष्ण पंडा और असम के वरिष्ठ भाकपा नेता असोमी गोगोई। मणिपुर का समूचा राज्य पिछले तीन महीने से जल रहा है और राज्य की जनता भारी संकट से गुजर रही है। प्रतिनिधिमंडल 21 अगस्त 2023 को इम्फाल पहुंचा और उनके दुख में हिस्सा बंटाने के लिए हिंसा से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। 22 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल ने चूड़ाचांदपुर और मोइरंग में विभिन्न राहत शिविरों का दौरा किया और शिविरों में रहने को मजबूर लोगों के दुख–दर्द और शिकायतों को सुना। प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें अपने पूरे समर्थन का विश्वास दिलाया। राज्य में हिंसा में जितनी बड़ी संख्या में लोग मरे हैं, संपत्ति की बर्बादी हुई है और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं–वह सब हृदयविदारक है। मोइरंग में प्रतिनिधिमंडल ने आजाद हिन्द फौज स्मारक पर जाकर नेताजी सुभाषचंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी। प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल अनुसूइया उइके से मुलाकात की और उन्हें जमीनी हालात की जानकारी दी। 23 अगस्त को प्रतिनिधिमंडल ने मणिपुर में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की 75वीं जयंती के संबंध में आयोजित मीटिंग में हिस्सा लिया जिसमें वक्ताओं ने मणिपुर की एकता के लिए जननेता हिजाम इराबोत के अद्वितीय योगदान का स्मरण किया।

प्रतिनिधिमंडल 24 अगस्त को मणिपुर से वापस लौटेगा।

ग़ैर–नेट छात्रवृत्ति ज़रूरतमंद छात्रों को नहीं मिल रही: भाकपा

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बिनोय विश्वम द्वारा उठाए गए सवाल पर शिक्षा मंत्री डॉ. सुभाष सरकार के लिखित जवाब पर कहा कि ''हमारे देश की एक बड़ी आबादी और उच्च शिक्षा में अत्यधिक नयूनतम नामांकन, सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, आशाप्रद नहीं है। कई योग्य शोधार्थी सहायता प्रक्रिया के अभाव में उच्च शिक्षा पूरी करने में असमर्थ हैं और गुणवत्ता शोध से युवा प्रतिभाओं का वंचित होना देश के लिए नुकसान है। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक योग्य शोधार्थी को इस तरह की छात्रवृत्ति हासिल करने का अवसर मिले।''

भाकपा नेता ने आगे कहा कि ''यह मामला मात्र फंड के आवंटन का नहीं है। इन छात्रवृत्तियों की समय पर अदायगी महत्वपूर्ण है कई छात्र अकसर छात्रवृत्तियों के देर से मिलने की कठिनाईयों का सामना करते हैं, जिसके कारण आर्थिक समस्याओं से जूझते हैं। छात्रवृत्ति भुगतान में देरी और प्रशासनिक अवरोध शोधार्थियों को एकाग्रचित हो शोध कार्य पूरा करने से रोकते हैं। सरकार को प्रक्रिया को सरल एवं कारगर बनाना चाहिए, छात्रवृत्ति को सार्वभौमिक बनाएं, महंगाई को ध्यान में रखते हुए समय पर छात्रवृत्ति बढ़ाएं ताकि शोधार्थी समय पर अपनी न्यायसंगत प्राप्य राशि प्राप्त कर सकें।

तिस पर भी, शिक्षा मंत्री ने जवाब में एम. फिल और पीएचडी शोधार्थियों की कुल संख्या और उनमें ग़ैर–नेट छात्रवृत्तियों का अनुपात, पिछले एक साल में ग़ैर–नेट छात्रवृत्ति में की गई बढ़त या छात्रवृत्ति बढ़ाने की सरकार की मंशा पर कुछ नहीं कहा। सरकार इस सवाल पर भी खामोश रही कि क्या गैर–नेट छात्रवृत्ति को सार्वभौमिक बनाया जाएगा।

शिक्षा मंत्री सुभाष सरकार ने राज्य सभा में बिनोय विश्वम द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में बताया कि वर्ष 2022–23 में देश भर में मात्र 16,270 शोधार्थियों को ग़ैर–नेट छात्रवृत्ति मिल रही थी। इनमें से एम. फिल में 873 और पीएचडी में 15, 397 शोधार्थी देश भर के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पंजीकृत हैं, यह आंकड़ा विश्वविद्यालय अनुदान द्वारा मुहैया कराया गया है।

यह भी बताया गया कि जेआरएफ और एसआरएफ में की गई बढ़त शोधार्थियों और छात्र संगठनों की उम्मीदों से कम है। जहां 2019 से 2023 की अवधि में जेआरएफ और एसआरएफ में बढ़ोतरी की गई थी, इन बढ़तों की आजीविका की बढ़ती लागत, महंगाई और बढ़ते शैक्षणिक दबाव के साथ तुलना करनी चाहिए जिसका सामना छात्र कर रहे हैं। छात्र जिन आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं उस दृष्टिकोण से पिछले चार सालों में जेआरएफ और एसआरएफ की बढ़त अपर्याप्त है खासतौर से एचआरएफ पर निर्भर होने के कारण समुचित छात्रवास के अभाव में।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम में संशोधन संघवाद पर हमला

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2023 पर राज्य सभा में 7 अगस्त 2023 को चर्चा के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पी. संदोष कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा बिल पेश करने की चर्चा पर इस बिल को अजनतांत्रिक, संघवाद–विरोधी और असंवैधानिक विधेयक कहा। उन्होंने आगे कहा कि, यदि आप इतिहास के पन्ने पलटाएंगे तो एक चीज आसानी से समझी जा सकती है एक नागपूर स्थित एक संगठन है, जिसका नाम वे नहीं लेना चाहते, वह संगठन शुरुआत से ही संघवाद की अवधारणा का विरोध कर रहा है। वे सोचते हैं कि संघवाद की अवधारणा वास्तविक रूप में भारत विरोधी है। इसलिए वह संगठन हमेशा संघवाद के विरूद्ध खड़ा हुआ है।

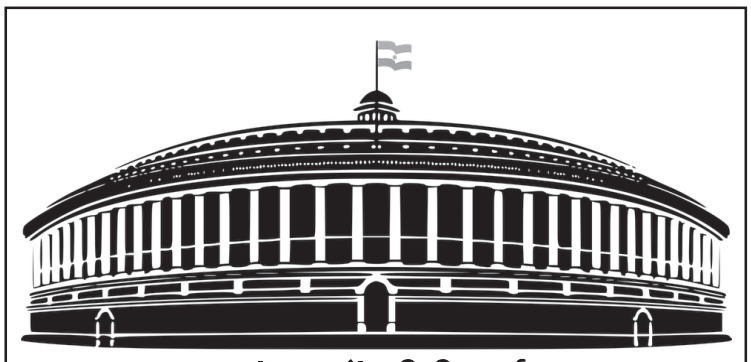

संसद में सीपीआई

संदोष कुमार ने कहा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सोचती है कि विधेयक के रूप में यह हमला, संघवाद पर जारी हमलों में एक नया हमला है। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों के वक्तव्यों की विस्तृत सूची का हवाला देते हुए संदोष कुमार ने कहा इस सूची में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी की कोई भी घटना न केवल दिल्ली के निवासियों को प्रभावित करती है बल्कि अन्तरराष्ट्रीय वैश्विक परिदृश्य में देश की प्रतिष्ठा, छवि, साख और गौरव को भी प्रभावित करती है।

सदन में मौजूद गृहमंत्री से भाकपा नेता ने पूछा कि क्या वे इस दृष्टिकोण को न्यायसंगत ठहराने के लिए क्या कोई एक उदाहरण दे सकते हैं। वास्तव में, मंत्री दिल्ली की जनता और जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का अपमान कर रहे हैं। जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार उत्तरदायी है और कोई भी इन मुद्दों पर अन्तरराष्ट्रीय मंच पर चर्चा नहीं करता।

संदोष कुमार पी. ने कहा कि दुर्भाग्यवश, कहना पड़ रहा है कि अन्तरराष्ट्रीय समुदाय मणिपुर पर चर्चा कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह कहते हुए उन्हें खेद है कि सत्ता पक्ष जो कि दिल्ली सरकार की असफलताओं पर मुखर है, उसे नोट करना चाहिए कि यूरोपीय यूनियन की संसद ने भारत के एक खास राज्य के बारे में चर्चा की। 6,500 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई, 500 लोग भी गिरफ्तार नहीं किए गए, तो एक राज्य में भाजपा सरकार हर तरह से विफल रही है और अब यह दिल्ली की केंद्र शासित क्षेत्र की सरकार को दोष दे रही है।

संदोष कुमार ने आगे कहा कि इस विधेयक के कई प्रावधान असंवैधानिक, संघीय–विरोधी हैं। कई भाजपा सांसद संभवतः कई कारणवश भाजपा में हाल में शामिल हुए हैं लेकिन कम से कम, उन्हें भाजपा के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करना चाहिए।

राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के पक्ष में थी, एल.के. आडवाणी, 2003 में भुला दिए गए भाजपा के नायक, ने दिल्ली को राज्य का पूर्ण दर्जा देने का सुझाव दिया था। भाजपा इन सब चीजों को भूल गई है। भाकपा नेता ने विधेयक पर अपना अवलोकन रखते हुए कहा कि दिल्ली विधेयक, वास्तव में, मुख्यमंत्री की स्थिति को चौथे दर्जे पर रखता है–पहले स्थान पर उप राज्यपाल, दूसरे पर सचिव, तीसरे पर कोई अन्य अधिकारी और चौथा स्थान मुख्यमंत्री। संदोष कुमार ने कहा कि इस स्थिति में क्यों हमें दिल्ली में जनतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार की जरूरत है और गृहमंत्री एक नया विधेयक दिल्ली प्रशासन के रद्दीकरण की पेशकश के लिए ला सकते हैं। यह सबसे बेहतर होता। हमारे कुछ दोस्त, खासतौर से उड़ीसा और आंध्रप्रदेश से, आज बहुत मुखर थे। प्रवर्तक निदेशालय ने आज उनके दरवाजे पर दस्तक न दी हो, लेकिन हमें ईडी से कोई डर नहीं है। हम इस विधेयक का भारत–विरोधी, जनतंत्र–विरोधी के रूप में विरोध करते हैं।

वोटों की राजनीति के लिये अलीगढ़ में भाजपा का जमघट

लखनऊ, 22 अगस्त 2023: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है कि कल श्री कल्याण सिंह की दूसरी पुण्यतिथि पर भाजपा द्वारा अलीगढ़ में किया गया जमावड़ा न तो हिन्दू गौरव जैसी कोई चीज था, न ही श्री कल्याण सिंह के प्रति सम्मान का प्रकटीकरण था। यह शुद्धतः एक चुनावी जमावड़ा था। यह धार्मिक प्रतीकों एवं जातीय आकांक्षाओं को उभार कर अंततः भाजपा के लिए वोट बटोरने के लिए किया गया भोंडा उपक्रम था। पुश्तैनी भक्तों को छोड़ कर हर किसी ने इसे इसी रूप में जाना– समझा है।

यहां जारी प्रेस वक्तव्य में भाकपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य डॉ. गिरीश ने कहा कि जनता से की गयी वादाखिलाफी, पूंजीपति/कार्पोरेटपरस्त और आमजन विरोधी नीतियों, महंगाई बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से जनता की तबाही, रुपये की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट, विदेशी निवेशकों द्वारा निवेश वापस लेने, सार्वजनिक संस्थानों की बिक्री, संवैधानिक संस्थाओं के संघीकरण, मणिपुर और नूंह जैसी घटनाओं की भयावहता एवं भाजपा शासित राज्यों में दमन और अत्याचार के चलते भाजपा के पैरों तले से जमीन खिसक चुकी है। अतएव विभाजन की राजनीति को हवा देकर, जातीय कशिश को उभार कर और थोक मात्रा में झूठ बोल कर यह भाजपा के 'बर्स्ट' (फट चुके) हो चुके टायर में हवा भरने का प्रयास था।

मंच से बीच बीच में श्री कल्याण सिंह का नाम लेना जरूरी था, लेकिन सारे भाषण मोदीजी की छवि उभारने और 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर कब्जा करने पर केन्द्रित थे। यदि भाजपा के मन में श्री कल्याण सिंह के प्रति इतना ही सम्मान था तो फिर क्यों उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, क्यों उन्हें राज्यपाल बना कर राजनीति की मुख्यधारा से काटा गया और क्यों उन्हें भाजपा छोड़ कर अलग पार्टी बनाने को मजबूर किया गया? डॉ. गिरीश ने सवाल खड़े किए हैं।

डॉ. गिरीश ने कहा कि भाजपा पर काबिज तिकड़ी अपने बड़े नेताओं के साथ 'यूज एंड थ्रो' (इस्तेमाल कर फेंक दो) का व्यवहार करती है। यह सभी जानते हैं, अतएव उन सबके नाम गिनाने की जरूरत नहीं है। आज वोटों के लिए उन्हे वे याद आ रहे हैं और जब स्वार्थ हल हो जायेगा तो भाजपा उनके सम्मान के साथ भी पुनः वही करेगी जो बहुतों के साथ कर चुकी है।

उन्होने हिन्दू गौरव की बात करने वालों से पूछा कि उनका यह गौरव तब कहां सोया हुआ था जब लोदी वंश, मुगल्स, अंग्रेज, पुर्तगाली और फ्रांसीसी भारत पर कब्जा कर रहे थे। जब सारा देश आजादी की जंग लड़ रहा था तो ये जिन्ना से साठगांठ कर दो राष्ट्र का सिद्धांत गढ़ रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत से पेंशन ले रहे थे और सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को हवा दे रहे थे। स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के खिलाफ इनकी गवाही और मुखबिरी को देश अभी तक भूला नहीं है।

राम मन्दिर निर्माण और बाबरी विध्वंस पर भी भाजपा निहित स्वार्थपरक और दोगली राजनीति करती रही है। बाबरी ध्वंस केस में बचने के लिये भाजपा नेता इसे आक्रोशित जनता का कृत्य और एक पूर्व प्रधानमंत्री का षडयंत्र बताते रहे, वहीं दूसरी ओर इसकी आड़ में नायकत्व गड़े जा रहे हैं। केन्द्र द्वारा सरकार को भंग किये जाने को 'बलिदान' के रूप में पेश किया जा रहा है। न्यायालय के आदेश और देश विदेश की जनता से एकत्रित विशाल चन्दे से निर्मित हो रहे श्री राम मन्दिर के निर्माण का श्रेय भाजपा खुद और मोदी जी को देने के लिये प्रपोगंडा कर रही है। वोटों और गद्दी के लिये विभाजन की राजनीति कर देश और समाज की एकता से खिलवाड़ कर रही है। ऐतिहासिक तथ्यों को चंद समय के लिये ढाँपा जा सकता है, इतिहास को बदला नहीं जा सकता।

देश और देश की जनता इन चालों को समझ चुकी है और वह अब भाजपा के झांसे में आने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी उनके हसीन ख्वाबों को पूरा नहीं होने दिया जायेगा, यह जनता का दृढ़ संकल्प है।

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

आर.एस. यादव

प्रधानमंत्री के मुख्य आर्थिक सलाहकार को संविधान से क्या तकलीफ

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष बिबेक देब रॉय ने 14 अगस्त 2023 को ''द मिंट'' में अपने एक लेख में भारत के संविधान को पूरी तरह बदलने की वकालत की है। इसमें उन्होंने लिखा है कि हमारा मौजूदा संविधान काफी हद तक 1935 के भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है। उस अर्थ में यह भी एक औपनिवेशिक विरासत है। अब इसे पूरा बदलने की जरूरत है।

उन्होंने लिखा है कि कुछ संशोधनों से काम नहीं चलेगा। हमें ड्राईंग बोर्ड पर वापस जाना चाहिए और पहले सिद्धांतों से शुरू करना चाहिए, यह पूछना चाहिए कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब क्या मतलब है।

उनके इस वाक्य से उनकी तकलीफ समझ में आ जाती है। उन्हें समाजवाद से तकलीफ है। उन्हें धर्मनिरपेक्षता से तकलीफ है। उन्हें लोकतंत्र से तकलीफ है। उन्हें न्याय, स्वतंत्रता और समानता से तकलीफ है। आखिर वे चाहते क्या हैं? यही न कि समाजवाद नहीं होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता नहीं होनी चाहिए; लोकतंत्र नहीं होना चाहिए; न्याय, स्वतंत्रता और समानता की बातें नहीं होनी चाहिएं। उन्हें संविधान से वही सब तकलीफें हैं जो आरएसएस और भाजपा को हैं।

उन्हें संविधान के ''बेसिक स्ट्रक्चर'' से भी बहुत तकलीफ है। वह कहते हैं कि ''भले ही संसद के जरिये लोकतंत्र कुछ भी चाहता हो, 1973 के बाद हमें बताया गया है कि इसके (यानी संविधान के) ''बेसिक स्ट्रक्चर'' को बदला नहीं जा सकता''।

उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय लॉ स्कूल के एक अविश्वसनीय एवं संदिग्ध अध्ययन का हवाला दिया है जिसके अनुसार लिखित संविधानों की औसत उम्र महज 17 साल पाई गई। उनका तर्क है कि भारत के संविधान को बने हुए 73 साल हो चुके हैं, अतः इसे बदला जाना चाहिए। अच्छा होता वह यह भी बता देते कि वह कौन से देश हैं जहां हर 17 साल बाद संविधान बदले जाते हैं या बदले गए हैं।

उन्हें संविधान में वर्णित राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों से भी बहुत तकलीफ है। उन्होंने लिखा है कि यदि सुधारों का संबंध बाजारों और सरकार की नए सिरे से फोकस की गई और घटी हुई भूमिका से है तो हमारे लिए राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों का क्या अर्थ रह जाता है?

उल्लेखनीय है कि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान को दिए गए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है ताकि वह उसके अनुसार काम करे और कानून एवं नीतियां बनाते समय उनका ध्यान रखे और एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करे। हालांकि वह कानून द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं (यानी किसी न्यायालय से लागू नहीं कराए जा सकते) परंतु देश के शासन के लिए इनका अत्यंत महत्व है और कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है।

ये अपेक्षा करते हैं कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक, व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देगा; राज्य सभी नागरिकों को आजीविका पर्याप्त साधन के अधिकार सुनिश्चित करने, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करने, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन–दौलत के संकेंद्रण को रोकने, पुरूषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा करने, बच्चों के बचपन एवं युवाओं का शोषण न होने देने, बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम करने, शिक्षा पाने और सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार प्रदान करने, काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने एवं मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करने, कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने, लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने, समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिणक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने जैसे कामों को सुनिश्चित करने की दिशा में काम करेगा।

संविधान के राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत सरकार को जन कल्याण की दिशा में काम करने का निर्देश देते हैं।

बिबेक देब रॉय एक ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री हैं। विद्वान भी हैं। उनसे आशा नहीं की जाती कि भारत के संविधान को औपनिवेशिक विरासत का नाम दें। उनसे आशा नहीं की जाती कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे शब्दों का अब मतलब पूछें। उनसे यह भी आशा नहीं की जाती कि कहें कि सुधारों की नीतियों ''राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांतों का क्या अर्थ रह जाता है?''

वह प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं। भले ही वह सफाई दें कि यह उनके अपने विचार हैं प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नहीं, परंतु उनके इस लेख में व्यक्त विचारों से उन तमाम लोगों के विचारों की अभिव्यक्ति होती है जिनके बीच रहकर वह काम कर रहे हैं। उनमें प्रधानमंत्री भी शामिल हैं, भाजपा और आरएसएस के अन्य नेता भी शामिल हैं। दरअसल वह उन्हीं लोगों के विचारों को आगे बढ़ रहे हैं। वह आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। परन्तु देश के लिए यह एक खतरनाक संकेत है कि सरकार के उच्चतम सतर पर संविधान को पूरी तरह बदलने पर चर्चा की जा रही है जिसकी अभिव्यक्ति देब रॉय ने की है।

एकेडेमिक स्वतंत्रता पर हमला

एक प्रतिष्ठित निजी विश्वविद्यालय–अशोक विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर सब्यसाची दास ने एक रिसर्च पेपर लिखा है जिसका शीर्षक है–डेमोक्रेटिक बैक स्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी (विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतांत्रिक गिरावट)। इस पेपर में उन्होंने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने कुछ ''इर्रेगुलर पैटर्न्स'' का पता लगाया है जिनसे भारत में लोकतंत्र के भविष्य के संबंध में चिंता पैदा होती है। सोशल मीडिया और एकेडेमिक सर्किलों में इस पेपर के आते ही अशोक विश्वविद्यालय की गवर्निंग बॉडी ने प्रो. दास के रिसर्च पेपर की जांच शुरू कर दी और उन पर किन्ही शक्तियों का इतना दबाव पड़ा कि उन्हें विश्वविद्यालय से त्यागपत्र देने को मजबूर होना पड़ा। इस घटना से खिन्न होकर विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के प्रोफेसर पी. बालकृष्णन ने प्रो. दास के रिसर्च पेपर के संबंध में अशोक विश्वविद्यालय की प्रतिक्रिया को ''एकेडेमिक स्वतंत्रता का उल्लंघन'' करार देते हुए त्यागपत्र दे दिया।

विश्व भर के लोकतंत्रों में चुनाव अध्ययन साहित्य के आधार पर पेपर में तर्क दिया गया है कि 2019 के भारत के लोकसभा चुनाव में जो ''इर्रेगुलेरिटी पैटर्न्स''(धांधलीपूर्ण तरीके) दिखाई पड़ते हैं उसके लिए दो बातों–''इलेक्टोरल मैनिपुलेशन'' (चुनावी जोड़तोड़) और ''प्रिसाइज कन्ट्रोल थीसिस'' (अचूक नियंत्रण थीसिस) को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

''प्रिसाइज कन्ट्रोल थीसिस'' का अर्थ है कि जिन चुनाव क्षेत्रों में कड़ा मुकाबला है'' उनमें ''अपनी बेहतर चुनाव मशीनरी'' की मदद से सही–सही अनुमान लगाने और फिर जीत के अंतर को प्रभावित करने की सत्ताधारी पार्टी की क्षमता एवं सामर्थ्य। इस मकसद के लिए पार्टी मतदान केंद्रों, विशेषकर बड़ी संख्या में मतदाताओं वाले शहरी मतदान केंद्रों को पार्टी अपने निशाने पर लेती है क्योंकि उन तक पहुंचना अपेक्षाकृत आसान होता है। इस बात का परिणाम इन मतदान केंद्रों पर बड़ी मात्रा में मतदान हो सकता है जिसके फलस्वरूप सत्ताधारी को बड़ी मात्रा में मतों के हिस्सा मिल जाता है।

दूसरी तरफ, ''इलेक्टोरल मैनिपुलेशन'' का अर्थ है स्थानीय स्तर पर चुनावी पक्षपात जिसे अंशतः चुनावी पर्यवेक्षकों द्वारा कमजोर मॉनिटरिंग के जरिये सुगम बनाया जाता है। इसमें किसी समुदाय, ग्रुप के वोटों का रजिस्ट्रेशन की शक्ल में और/या पड़े मतों के जोड़तोड़ की शक्ल में रणनीतिक/ लक्षित दमन शामिल है। यह बात चुनावी फ्रॉड होती है और इससे इलेक्टोरल इन्टेग्रिटी (चुनावी सत्यनिष्ठा) के संबंध में गंभीर प्रश्न पैदा होते हैं।

इस पेपर में 2019 के लोकसभा के चुनाव में कुछ गंभीर अनियमितताओं की तरफ इंगित किया गया है जिससे भाजपा को फायदा पहुंचा। भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइट के डाटा को इस्तेमाल करते हुए पेपर में ऐसे 59 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों का जिक्र किया गया है जहां जीतने वाले और हारने वाले उम्मीदवार के मतों में केवल 0.05 प्रतिशत का अंतर था। इन 59 चुनाव क्षेत्रों में से 41 में भाजपा के उम्मीदवार जीते। जिन राज्यों में भाजपा सत्ता में थी वहां के ऐसे 27 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों से 22 में भाजपा के उम्मीदवार जीते। इन चुनाव क्षेत्रों में, जहां मुस्लिम निर्वाचक वर्ग (यानी मतदाता) बड़ी मात्रा में थे, वहां चुनाव मतदान केंद्रों पर अधिक मतदान के रूप में विसंगति दृष्टिगोचर थी जिससे यह ''अनियमितता'' का मामला बनता था। पेपर में भारत के चुनाव आयोग की वेबसाइटों, सीएसडीएस (सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डवलपिंग सोसायटीज), पोस्ट पोल सर्वे और प्रकाशित पेपर्स जैसे ''स्टैंटर्ड स्रोतों'' से जमा डाटा को इस्तेमाल किया गया है और बताता है कि इस ''पैटर्न ऑफ इर्रेगुलेरिटी'' (धांधली के तरीके) की व्याख्या प्रिसाइज कन्ट्रोल थीसिस से की जा सकती है।

अन्य अनियमितताओं के अलावा पेपर में चुनावों के सात चरण में से पहले चरण के लिए प्रत्येक लोकसभा चुनाव क्षेत्र में ''ईवीएम वोटों की अंतिम गिनती'' जो चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पर जारी की थी और ''चुनाव क्षेत्रवार ईवीएम में वोटों की संख्या ''जो बाद में जारी की गई, के बीच फर्क का हवाला दिया गया है। मीडिया द्वारा इस पर सवाल किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट से पहले की संख्याओं को हटा दिया।

पेपर में कहा गया है कि मतदान केंद्रों पर तैनात चुनाव अधिकारी रजिस्टर्ड मतदाताओं को मतदान की इजाजत देने में काफी ''डिस्क्रेशन'' (सव–विवेक) का इस्तेमाल करते हैं। पेपर बताता है कि मतदाता सूची में अपने नामों के साथ मुस्लिम मतदाताओं आसानी से पहचान हो जाती है और उन्हें मतदाता सूची से नाम हटाए जाने और भेदभाव किए जाने, दोनों बातों का शिकार बनाया जाता है। पेपर में दावा किया गया है कि भाजपा शासित राज्यों में जिन मतदान केंद्रों में काफी संख्या में मुस्लिम मतदाता थे, वहां ऐसा हुआ क्योंकि राज्य सरकार वहां तय कर सकती थी कि मतदान केंद्र के इंचार्ज अधिकारियों के तौर पर किसे नियुक्त करना है। पेपर में ''मतों की गणना की कमजोर मॉनिटरिंग'' के लिए चुनाव आयोग की भूमिका पर भी उंगली उठाई गई। लेखक ने यह आरोप लगाने के लिए 543 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में से 539 चुनाव क्षेत्रों, जिनमें 1,704 ''काउटिंग आर्ब्जवर्स'' (मतगणना परिवेक्षक) थे, के डाटा तक अपनी पहुंच होने का दावा किया है।

कुल मिलाकर अध्ययन से इशारा मिलता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने चुनावी धांधली कर बहुमत हासिल किया था।

प्रो. दास का रिसर्च पेपर इस प्रकार का संभवतः पहला अध्ययन है। लगता है इससे सरकार बौखला गई है। ''द वायर'' की 22 फरवरी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार गुप्तचर विभाग के अधिकारी 21 फरवरी को प्रो. दास से मिलने के लिए अशोक विश्वविद्यालय पहुंचे परंतु वह नहीं मिले क्योंकि वह पुणे गए हुए थे।

गुप्तचर विभाग के अधिकारियों के अशोक विश्वविद्यालय जाने की खबरों पर एकेडेमिक क्षेत्रों में जबर्दस्त आलोचना हो रही है। अमेरीका के मेसाचुसेट्स की प्रोफेसर और ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्री जयति घोष की प्रतिक्रिया थी कि ''अब तो बेहदूगी की हद हो गई है।'' नेहरू स्मारक म्युजियम एवं पुस्तकालय की पूर्व डायरेक्टर और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के

शेष पेज 15 पर...

राजस्थान भाकपा की विधानसभा चुनावों के लिए निर्णायक बैठक

उदयपुर: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजस्थान की दो दिवसीय राज्य परिषद की बैठक 19–20 अगस्त को उदयपुर में सम्पन्न हुई। जिसमे प्रदेश के सभी जिलों से आए 45 राज्यपारिषद सदस्यों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता साथी सुभाष श्रीमाली एवं सूरजभान सिंह एडवोकेट ने की। जिसमे पार्टी के राष्ट्रीय नेता एवं राज्य पर्यवेक्षक डॉ. गिरीश शर्मा उपस्थित रहे। बैठक में राज्य सचिव नरेंद्र आचार्य, उदयपुर से राज्य परिषद सदस्य जिला सहायक सचिव हिम्मत चांगवाल एवं घनश्याम सिंह तावड के साथ साथ आमंत्रित रूप में प्रीतम जोशी, गेबीलाल डामोर, कमजी मीणा ने भी भाग लिया।

दो दिवसीय मीटिंग में देश की राष्ट्रीय राजनीतिक, आर्थिक, स्थिति अनुसार राज्य में पार्टी की भूमिका, राज्य की राजनीतिक स्थिति तथा राज्य की जनता के सामने मौजूद प्रमुख सवाल तथा राज्य के आगामी चुनावों को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा की गयी और निर्णय लिए गए।

राज्य परिषद मीटिंग देश की राजनीतिक स्थिति में नरेंद्र मोदी सरकार की घौर दक्षिणपंथी सरकार जिसके चलते देश के संविधान, संवैधानिक संस्थाओं पर हमले राष्ट्र को सांप्रदायिक आधार पर विभाजित करेक हिन्दू राष्ट्र की दिशा में ले जाने की नीतियों की कड़ी आलोचना की। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार शिखर पर हैं। देश में मणिपुर जल रहा है, हरियाणा के नूंह मेवात सांप्रदायिकता की आग में धकेलने की घटनाएँ बढ़ रहीं हैं जिसे सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की सीधी शह और समर्थन प्राप्त है।

देश के सामने उत्पन्न गंभीर स्थिति से देश को निजात दिलाने के लिए देश की धर्मनिरपेक्ष जनवादी वामपंथी पार्टियों ने एक विकल्प के तौर पर इंडिया का गठन किया है जो की एक सकारात्मक कदम है जिसका आह्वान है–भाजपा हटाओ, देश बचाओ। इससे देश के आमजन में आशा की उम्मीद जगी है।

राज्य परिषद ने तय किया है कि देश की राजनीति में आए सकारात्मक बदलाव को ध्यान में रखते हुए राज्य विधानसभा चुनाव की रणनीति तय करने का फैसला किया है। पार्टी ने राज्य में उपस्थिति सुनिश्चित करने, पार्टी का जनाधार बढ़ाने, राज्य विधानसभा में लोक हितेशी शक्तियों की संख्या बढ़ाने तथा राज्य में धर्मनिरपेक्ष सरकार बनने की दिशा में काम करने का निर्णय लिया। इसी को ध्यान में रख कर पार्टी अपने जनाधार वाले 20 क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी। पार्टी राज्य में वामपंथी जनवादी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों से आपसी तालमेल करने का प्रयास करेगी।

राज्य पारिषद में राज्य की राजनैतिक स्थिति का मूल्यांकन किया और जनता के सामने आ रहे मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए। पार्टी ने नोट किया की हालांकि अशोक गेहलोत की कांग्रेस ने चुनाव के अंतिम वर्षो में अनेक लोक हितेषी कल्याणकारी घोषणाएँ की है और उनका जनता में सकारात्मक प्रभाव भी है लेकिन वित्तीय अभाव, समय की कमी तथा भ्रष्टतंत्र के चलते ये योजनाएँ कितनी कारगर साबित होगी इसमे संदेह है क्योंकि राज्य पहले से ही 4 लाख करोड़ के कर्ज में है। राज्य परिषद ने राज्य में महिला अत्याचार बालिकाओं से बलात्कार की घटनाएँ लगातार बढ़ रही हैं। नूंह मेवात की घटनाओं से राज्य में सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। हाल ही में हुई मोब लिंचिंग से हुई हत्या गंभीर चिंता का विषय है। एसी घटनाएँ पहले भी होती रही है। राज्य परिषद ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की और उसके खिलाफ संघर्ष का निर्णय लिया है। राज्य परिषद ने आदिवासी क्षेत्र की समस्याओं को चिन्हित किया। आदिवासी इलाके में आदिवासी के जल जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा, आदिवासियों के जमीन के पट्टे प्रमुख सवाल है जिनके लिए पार्टी लड़ेगी। मेवाड़ क्षेत्र में गेम सेंक्चुरी के नाम से 128 गावों के लोगों की रोजी रोटी, साथ साथ विस्थापन का खतरा मंडराया हुआ है। पार्टी इसका विरोध करती है।

राज्य पार्टी ने टीएसपी व अन्य आरक्षित वर्ग के पदों पर न्यायालय द्वारा लगी रोक पर गंभीर चिंता व्यक्त की तथा राज्य सरकार से मांग की है कि राजस्थान विधानसभा से नियम बदल कर उनकी पैरवी कर के टीएसपी के अधिकार की रक्षा करें।

राज्य परिषद ने निर्णय किया कि राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के ज्वलंत मुद्दों को ले कर पार्टी संघर्ष करेगी। राज्य और राज्य में महंगाई और बेरोजगारी भ्रष्टाचार एवं महिला एवं दलित अत्याचार तथा सांप्रदायिकता के खिलाफ संघर्ष करेगी। राज्य परिषद में राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में पारित राकोका एवं शव सम्मान विधेयक पारित करने की आलोचना की और इसे वापस लेने की मांग की क्योंकि ये कानून जनता के जनतांत्रिक अधिकारों पर हमला हैं। पार्टी राज्य परिषद संगठन को मजबूत एवं सक्रिय करने, नए क्षेत्र मे पार्टी जनसंगठनों विशेषकर किसान, सभा आदिवासी महासभा, छात्र एवं महिला संगठन खड़े करने की कार्य योजना बनाई है। छात्र संगठन एवं एआईएसएफ राज्य स्तरीय कन्वेन्शन 10 सितंबर को जोधपुर में तथा किसान सभा का कन्वेन्शन भी 10 सितंबर को जयपुर में करने का निर्णय किया, साथ ही 24 अगस्त को नई दिल्ली में किसान–मजदूर संयुक्त कन्वेन्शन में भाग लेने का निर्णय किया है।

राजनीतिक कार्यकर्ता का अपहरण एवं हत्या बहुत ही चिंताजनक: भाकपा

पटना: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मधुबनी जिला परिषद द्वारा 22 अगस्त 2023 को पार्टी नेता कलुआही के अंचल मंत्री रामटहल पूर्वे के हत्याकांड संख्या 93/23 के अपराधियों को चिन्हित कर गिरफ्तार करने में विफल मधुबनी पुलिस के खिलाफ समाहरणालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। विगत 5 मई 2023 को रामटहल पूर्वे का अपहरण कर हत्या कर दी गई एवं उनका शव गांव के आगे झाड़ी में सड़क किनारे 8 मई 2023 को फेंक दिया गया। लगभग साढ़े तीन महीने बीत जाने के बाद भी आजतक अपराधियों की पहचान करने में कलुआही पुलिस विफल रही है।

धरनास्थल पर उपेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक सभा की गई। सभा संबोधित करते हुए भाकपा के राज्य सचिव एवं पूर्व विधायक रामनरेश पाण्डेय ने कहा कि राजनीतिक कार्यकर्ताओं का अपहरण एवं हत्या बहुत ही चिंताजनक बात है। भाकपा ने आंदोलन एवं संघर्ष के बदौलत लाखों परिवारों को बासगीत पर्चा एवं सैकड़ों गांव बसाए। जरूरतमंदों को दबंगों के जुल्म एवं अन्याय से बचाने का काम भाकपा करती रही है।

रामनरेश पांडेय ने कहा कि रामटहल पूर्वे की हत्या उसी आंदोलन एवं संघर्ष में दबंगों द्वारा की गयी है। 85 वर्ष की उम्र में भी वे दिन रात गरीबों के लिए काम करते थे। लेकिन अपराधियों की बढ़ती अपराधिक मनोवृति एवं पुलिस का अपराधियों के उपर कम होते हुए खौफ के कारण जिले में लगातार घटनाओं में वृद्धि हो रही है। रामटहल पूर्वे के हत्यारों को गिरफ्तार करने में विफल पदाधिकारियों के ऊपर करवाई की जानी चाहिए। धरने को संबोधित करते हुए जिला मंत्री मिथिलेश झा ने कहा मधुबनी जिले में अपराधी बेलगाम बन चुके हैं। अपराधियों के साथ पुलिस की मिलीभगत आम चर्चा का विषय है। रामटहल पूर्वे की हत्या एक निंदनीय घटना है। लेकिन मधुबनी पुलिस प्रशासन द्वारा कलुआही थाना कांड संख्या 93/23 को जिस रूप में समाप्त करने की बहुत बड़ी साजिश की जा रही है भाकपा चुप नही बैठेगी। आज का धरना प्रदर्शन इस बात का संकेत है की यदि अभी भी एक नियत समय सीमा की अंदर कांड का उद्भेदन एवं गिरफ्तारी नही की जायेगी तो जिला कमेटी की बैठक में अगले आंदोलन की तैयारी की जायेगी। जरूरत हुई तो भाकपा जिला नेतृत्व अनशन पर भी बैठने को विवश होगा। जब तक कांड का उद्भेदन एवं दोषी पदाधिकारी पर कारवाई नही होगी भाकपा का आंदोलन चलता रहेगा। धरने को पार्टी राष्ट्रीय परिषद सदस्य राजश्री किरण, राज्य परिषद सदस्य कृपानंद आजाद, रामनारायण यादव, सूर्यनारायण महतो, राकेश कुमार पांडेय, किरनेश कुमार, पार्टी जिला के नेतृत्वकारी साथी रामनारायण बनरैत, ह्रदय कांत झा, मो जहागिर, राजेश कुमार पांडेय, हरिणाथ यादव, मातवर सहनी, मंगल राम, आनंद कुमार झा, तिरपित पासवान, अशेश्वर यादव, शनिचरी देवी, उमेश पांडेय, मोतीलाल शर्मा, विनय चंद्र झा, हरिनारायण सदाय, संतोष कुमार झा, जलेश्वर ठाकुर, जुबेर अंसारी, अजय कुमार वर्मा, रतीश झा, सत्यनारायण यादव, राहुल कुमार, राजगीर पूर्वे, प्रशांत रंजन, श्याम पूर्व सहित सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओ ने धरने में भाग लिया। धरने के बाद एक ज्ञापन पुलिस अधीक्षक एवं जिला समाहर्ता को सौंपा गया। अगर नियत समय सीमा के अंदर कांड का उद्भेदन नही किया गया तो पार्टी आगे के आंदोलन पर विचार करेगी।

भारतीय खेत मजदूर यूनियन तमिलनाडु का राज्य सम्मेलन संपन्न

पी गणेशन

विरूद्धुनगरः भारतीय खेत मजदूर यूनियन, तमिलनाडु राज्य का 13वॉ अधिवेशन 28–30 जुलाई 2023 को तमिलनाडु के विरूद्धुनगर जिले के राजपालयम में पी एम रामसामी यादगार भवन में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता पूर्व विधयक के. तंगमणी, पूर्व विधयक पी पदमावती, वी पी पल्लनिसामी, ए एल रासु और पूंकोडी के अध्यक्षमंडल ने की।

विलुप्पुरम में पिछले अधिवेशन स्थल से के एस अप्पाऊ के नेतृत्व में लाये गए झंडे को जी कृष्णन ने ग्रहण किया और सम्मेलन स्थल पर वरिष्ठ नेता पूर्व विधयक जी पल्लनिसामी, ने भारतीय खेत मजदूर यूनियन का झंडा फहराया।

स्वागत समिति के अध्यक्ष पी लिंगम पूर्व सांसद ने सम्मेलन में आए डेलिगेटों का स्वागत किया।

भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महासचिव गुलजार सिंह गोरिया ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। एआईएडब्ल्यू के राज्य सचिव अमिर्दलिंगम, एटक के राज्य महासचिव एम राधाकृष्णन, आल इंडिया किसान सभा के राज्य महासचिव पी एस मासिलामणी, जीवन बीमा के राज्य सचिव एम वीरपांडियन, आल इंडिया ग्रामीण कृषि श्रमिक यूनियन के राज्य सचिव पालसुन्द्रम ने सम्मेलन का अभिनंदन किया।

संगठन के राज्य महासचिव पूर्व विधयक एन पेरियासामी ने पिछले पाँच साल के कामकाज की रिपोर्ट पेश की। जिस पर 34 डेलिगेटों ने बहस में हिस्सा लिया। अतं में विभिन्न सुधारों के साथ रिपोर्ट को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

दूसरे दिन मनरेगा कानून की उपलब्धियों, चुनौतियों एवं समाधान पर सेमिनार हुआ। सेमिनार की अध्यक्षता एटक अध्यक्ष टी एम मूर्ति ने की। ग्राम पंचायत प्राधिकरण और श्रमिकों के अधिकार विषय पर प्रो जी पलानिथुराई, कानून को तोड़ने के प्रशासकों का विरोध करने के दायित्व विषय पर वहिदा निजाम और स्थानीय शासन प्रशासन से मिले अनुभव और सबक विषय पर ए भास्कर ने बात की।

संगठन के राज्य कोषाध्यक्ष एस चंद्रकुमार ने आय–व्यय का विवरण पढ़ा। सम्मेलन ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। जी वेंकटाचलम ने सम्मेलन में भाग लेने वाली प्रतिनिधियों की योग्यता पर रिपोर्ट पढ़ी।

सम्मेलन में पी गणेशन, ए भास्कर, जे प्रतापन, के भास्कर, एस महेंद्रन और प्रताप चंद्रन द्वारा नीचे दिए प्रस्तावों को सम्मेलन ने सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

तमिलनाडु सरकार से अनुरोध किया गया कि खेत मजदूरों की समाजिक–आर्थिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए खेत मजदूरों की प्रतिनिधियों को शामिल करके एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

पिछले 1996–2001 में डॉ. करुणानिधि शासन के दौरान में खेत मजदूरों के लिए स्थापित कल्याण बोर्ड की तरह फिर से बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए।

छोटे और सीमांत किसानों सहित खेत मजदूरों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने के लिए अलग पेंशन कानून पारित किया जाना चाहिए।

खेत मजदूरों के लिए केंद्रीय कानून बनाने,

मनरेगा बजट बढ़ाने और साल में कम से कम 200 दिन काम और 600 रुपये प्रतिदिन मजदूरी देने

भूमिहीनों को आवास के लिए 8 डिस्मिल जमीन और 400 वर्ग फीट स्थल पर पक्का मकान बनाने के लिए छह लाख रुपये अनुदान दिया जाए।

पहाड में रहते हुए महिलाओं को तमिलनाडु सरकार की उपनगरीय बसों में मुफ्त यात्रा का विस्तार किया जाना चाहिए।

भूमिहीन श्रमिकों के परिवार और पहाड के लोगों के परिवारों के राशन कार्डो को एएओई राशन कार्ड की तरफ बदला जाना चाहिए।

तमिलनाडु सरकार को आदिवासियों के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा प्रदान की गई पोषण पैकेज प्रदान करने की योजना को लागू करना चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों में शिक्षित युवाओं को स्वरोजगार यात्रा व्यवसाय के लिए प्रत्येक परिवारों को दस लाख रुपये का 100 प्रतिशत सब्सिडी अनुदान दिया जाता है। उस की तरफ तमिलनाडु में अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवारों को विशेष घटक निधि पर आधारित दस लाख की पूरी तरह से सब्सिडी वाली निवेश सहायता योजना को विकसित और कार्यान्वित करने का अनुरोध किया गया।

सम्मेलन ने 101 सदस्य राज्य समिति और 21 सदस्य राज्य विकास–उद्योग निवेश सहायता योजना लागू करना चाहिए।

तेलंगाना राज्य में दलित बंधु योजना शुरू की गई है। इस योजना के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति

कार्यकारणी का चुनाव सर्वसम्मति से किया गया। पूर्व विधयक एन पेरियासामी को भारतीय खेत मजदूर यूनियन का राज्य अध्यक्ष, विधायक के मारिमुद्तु, पूर्व विधयक पी पदमावती और ए वरदराजन को उपाध्यक्ष, ए भास्कर को महासचिव चुना गया और वी पी पल्लनिसामी, जे प्रतापन और एस महेंद्रन सचिव चुने गये और चंद्रकुमार को कोषाध्यक्ष चुना गया।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य सचिव आर मुतरासन ने सम्मेलन का अभिनंदन किया और सम्मेलन को समापन किया।

शाम को सम्मेलन में लिए गए माँगों समझाने के लिए पी सेथुरामन स्मारक स्थल पर एक आम सम्मेलन आयोजित की गयी। आम सम्मेलन की अध्यक्षता टी पूर्व विधायक रामसामी ने की उसमें भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महासचिव गुलजार सिंह गोरिया, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव आर मुतरासन, पर्वु विधयक एन पेरियासामी, सांसद (लोकसभा) एम सेलवरासु, पूर्व विधायक जी. पल्लनिसामी, एम वीरपांडियन, ए भास्कर, पूर्व विधायक पी पदमावती, विधायक के मारिमुद्तु, पूर्व सांसद पी लिंगम ने सम्मेलन के प्रस्तावों को समझाया और संबोधित किया।

राजपालयम और विरुद्धुनगर जिले के पूरे शहरों में गली को यूनियन के ध्वजों और बैनरों से सजाया गया था। रैली में हजारों खेत मजदूरों ने भाग लिया।

हरियाणा में समाज का सांप्रदायिकरण बंद करो

नई दिल्लीः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिवमंडल ने 11 अगस्त 2023 को निम्नलिखित बयान जारी कियाः

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय सचिवमंडल इस रिपोर्ट पर चिंता व्यक्त करता है कि हरियाणा में कई ग्राम पंचायतों ने मुस्लिम दुकानदारों और विक्रेताओं को अपना व्यवसाय करने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव पारित किया है। यह सामाजिक बहिष्कार के समान है और समाज के सांप्रदायिकरण के लिए उकसाने वाला है।

पार्टी मांग करती है कि ऐसी संविधान विरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए और उम्मीद है कि हरियाणा सरकार इस तनावपूर्ण स्थिति में अल्पसंख्यकों को पूरा समर्थन और सुरक्षा प्रदान करेगी।

गुजरात में प्रगतिशील लेखन: एक विहंगावलोकन

रामसागर सिंह परिहार

1917 की सोवियत समाजवादी क्रांति का दुनिया भर में प्रभाव पड़ा। भारत देश और गुजरात उससे अछूता नहीं रह सका, सोवियत क्रांति का गुजरात के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर जबरजस्त प्रभाव पड़ा और राजनीतिक और सामाजिक जीवन प्रभावित हो तब साहित्य प्रभावित हुए बिना कैसे रह सकता है और हुआ भी यही।

यही कारण है कि उस समय के साहित्यकारों के साहित्य में समाजपक्षी, यथार्थवादी प्रगतिशील साहित्य के दर्शन होते हैं। "कोयाभागत की कड़वी वाणी और गरीबों के गीत" गुजरात के प्रगतिशील साहित्यकार "सुन्दरम" की प्रतिनिधि रचना मानी जाती है। उसमें उन्होंने दलित विधवा मकोरबाई की व्यथा कथा का वर्णन किया है, साथ ही साथ उसके दु:ख से द्रवित होते हैं और क्रुद्ध होकर ईश्वर को बैकुण्ठ चले जाने की मांग करते हैं। इस पुस्तक की प्रस्तावना (1932,जब प्रगतिशील लेखक की स्थापना भी नहीं हुई थी) में वह लिखते हैं कि 'दुनिया के एक देश (रूस) ने इन चीजो ईश्वर, गरीबी, बेकारी और भुखमरी से निजात पा ली है जबकि हम तो इन सबके व विषय में अभी तक विचार भी नहीं करते हैं।

इसी तरह 1932 में ही वीसापुर जेल में उमाशंकर जोशी ने अपनी प्रसिद्ध कविता "भूख्या जणोनी जठराग्नि जागशे, खान्डेर नी भष्म कणी न लाघशे" अर्थात जब भूखे लोगों की भूख जगेगी तब महलों की राख का एक कण भी नहीं मिलेगा। इसी समय में गुजराती के साहित्यकार चन्द्रभाई का उपन्यास 'भट्टी' गुजरात के छारा जाति जिसे अंग्रेज सरकार अपराधी मान खुली जेल में रखती थी, की व्यथा कथा पर आधारित था। जिसके प्रकाशन के बाद उसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। बाद में आजादी मिलने के बाद अहमदाबाद की पीपुल्स बुक हॉउस ने इसका पुनर्प्रकाशन किया था। 1935 में अहमदाबाद में नवी दुनिया प्रकाशन संस्था का अहमदावाद में प्रारंभ हुआ जिसका उद्देश्य प्रगतिशील साहित्यकारों की कृतिओं का प्रकाशन करना था और इसी क्रम में गुजराती के प्रगतिशील साहित्यकार बकुलेस के कहनी संग्रह "विश्वास" का प्रकाशन किया गया था। इस कहानी संग्रह की प्रस्तावना उस समय के गुजराती के प्रसिद्ध साहित्यकार रविशंकर मेहता ने लिखी थी। 1920से 1935 के दौरान जो साहित्यिक आन्दोलन गुजराती साहित्य में चला उससके चलते गुजराती के साहित्यकारों ने मानववादी, यथार्थवादी और प्रगतिशील साहित्य का सर्जन किया।

जब 1936 के अप्रैल महीने की 11 तारीख को लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का स्थापना अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता उर्दू–हिंदी के साहित्यकार प्रेमचंद ने की और उसमें यादगार उद्‌गार व्यक्त किये। उस राष्ट्रीय अधिवेशन में इन्दुलाल याज्ञिक, जशु मेहता, भोगीलाल गाँधी हिरानन्द गोलवाला ने गुजरात का प्रतिनिधित्व किया था। इस अधिवेशन में गुजराती के मूर्धन्य साहित्यकार उमाशंकर जोशी और राष्ट्रीय शायर झबेरचंद मेघाणी को भी जाना था लेकिन आर्थिक कारणों से नहीं जा सके थे। समय की मांग और मुंशी प्रेमचंद के भाषण का देशभर के साहित्यकारों पर जबरजस्त प्रभाव पड़ा। गुजराती के साहित्यकार भी उससे अछूते नहीं रह सके।

5 जुलाई 1936 को राज्यभर के साहित्यकारों का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ और उस समय के गुजराती साहित्य के जाने माने विवेचक नवलाराम त्रिपाठी की अध्यकता में गुजरात में प्रगतिशील लेखक मंडल की स्थापना हुई। इसी तरह 1938 के जनवरी महीने की 9 तारीख को अहमदाबाद में ही फिर सम्मेलन हुआ जिसमें साहित्यकार रमण लाल वसंतलाल देसाई गुजरात प्रगतिशील लेखक मंडल के अध्यक्ष चुने गए। इससे पहले गुजरात में 1935 में नवी दुनिया प्रकाशन संस्था का अहमदावाद में प्रारंभ हुआ जिसका उद्देश्य प्रगतिशील साहित्यकारों की कृतियों का प्रकाशन करना था और इसी क्रम में गुजराती के प्रगतिशील साहित्यकार बकुलेस के कहनी संग्रह "विश्वास" का प्रकाशन किया गया था इस कहानी संग्रह की प्रस्तावना उस समय के गुजराती के प्रसिद्ध साहित्यकार रविशंकर मेहता ने लिखी थी। 1949 तक राज्य में प्रगातिशील आन्दोलन अपने चरमोत्कर्ष पर चलता रहा। गुजराती लेखन आन्दोलन पर चर्चा करते समय यह अवश्य ध्यान रखना होगा कि गुजराती साहित्य का सृजन गुजरात में ही नहीं वरन गुजरात के बाहर मुंबई और कलकत्ता में भी गुजराती साहित्य का सृजन होता था।

15 अगस्त 1947 को देश को आजादी मिली। आजादी मिलने के बाद की स्थिति में लेखकों और साहित्यकारों में एक विशेष प्रकार का आत्ममंथन प्रारंभ हुआ, जिसमें साहित्यकारों के एक वर्ग का मानना था कि देश की आजादी मिलने के बाद परिस्थिति बदल गयी हैं क्योंकि हमारे अपने लोग अब शासन चलाते हैं और वह लोग देश की इन समस्याओं को अच्छी तरह समझते हैं वह लोग इन समस्याओं का निराकरण करेंगे। और गुजरात में गाँधी और सरदार पटेल और के एम मुंशी का समाज, राजनीति और साहित्य पर बड़ा प्रभाव था और प्रगतिशील लेखन आन्दोलन के विषय में उनकी राय अच्छी नहीं थी। इस तथ्य को मद्देनजर रखते हुए गुजरात में अधिकतर साहित्यकारों ने प्रगतिशील साहित्य आन्दोलन से किनारा करते हुए शासन की तरफ रूख कर लिया। दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादियों और कम्यूनिस्टो के बीच जो कटुता पैदा हुई उसका प्रभाव सबसे अधिक गुजरात में पड़ा और समाजवादियों से जुड़े साहित्यकारों का एक बड़ा खेमा प्रगतिशील लेखन आन्दोलन से अलग हो गया और कुछ तो प्रगतिशील लेखन आन्दोलन के विरोधी हो गए थे।

जो साहित्यकार प्रगतिशील लेखन आन्दोलन की सरपरस्ती भी करते थे उन्होंने भी प्रगतिशील साहित्य के मापदंडो को अत्यंत कठोर कर दिया। उन्होंने मुशी प्रेमचंद के भाषण और सज्जाद जाहिर की नसीहतो को दरकिनार करते हुए प्रगतिशील साहित्य और प्रगतिवादी साहित्य के अंतर को भुला दिया। इससे जो परिणाम आया वह अवश्यंभावी था क्योकि संकुचितावाद बहुत सारे नवोदित साहित्यकारों को प्रगतिशील साहित्य आन्दोलन से खारिज कर दिया गया या फिर उन्होंने स्वत: दूरी बना ली थी।

इन सब कारणों के बावजूद भी लम्बे समय तक गुजरात में साहित्यकार बड़ी संख्या में प्रगतिशील लेखन आन्दोलन से जुड़े रहे। उन सभी के नाम इस लेख में स्थानाभाव के कारण देना संभव नहीं है। फिर भी कुछ नामो को याद करना जरुरी है गुजरात के प्रगतिशील लेखन आन्दोलन में शिरकत करने वालों मे सुन्दरम उमाशंकर जोशी, जयंत खत्री, बकुलेस, जीतू मेहता, इन्दुलाल याज्ञिक, भोगीलाल गाँधी, रमण वसन्तलाल देसाई, झवेरचंद मेघाणी, गुणवंत आचार्य, पुष्कर चंद्रावरकर, जसवंत ठाकर, बटुक देसाई, चंद्रभाई भट्ट, शेखादम आबुवाला, शंकर पंड्या, प्रेमनाथ मेहता, शंकर पंड्या, धनवंत ओझा, हिम्मत खटसुरिया और दिलीप राणपुरा मुख्य थे। गुजरात में गुजराती साहित्य के साथ साथ उर्दू साहित्य भी प्रगतिशील लेखन आन्दोलन गुजरात प्रगतिशील लेखक मंडल का भाग रहा। तब प्रगतिशील लेखक संघ को गुजारत में प्रगतिशील लेखक मंडल कहा जाता था। जोकि प्रगतिशील लेखन की प्रव्रत्तियो से खूब प्रभावित हुआ था। उस समय के उर्दू के साहित्यकारों में तबस्सुम मुबारक पुरी, जब्बार हुसेन अहमद, वहीद बनारसी, जावेद अंसारी मुख्य थे। यह सब साहित्यिक कृति रचते थे लेकिन अभी तक गुजरात में उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना नहीं हुई थी।

8 फरवरी 1947 को अहमदाबाद के मिर्जापुर स्थित कुरेश जमात के ऑफिस में उर्दू के साहित्यकारों की एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें तबस्सुम मुबारकपुरी, जब्बर हुसैन 'अहमद', जमील कलीमी, महमूद माइल, वारिस हुसैन अल्वी और जावेद अंसारी सहित बड़ी संख्या में साहित्यकार और साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे थे। मीटिंग में लंबी जद्दोजहद के बाद उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की गयी और प्रो. वारिस हुसैन अल्वी को उसका सचिव चुना गया। साथ ही साथ इस मीटिंग में उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ का एक संकल्पपत्र भी स्वीकृत किया गया था जो कुछ इस प्रकार था: "हम साहित्यकार देश की उदात्त संस्कृति के वारिस होने का दावा करते हैं, नया जीवन सुन्दर बने इसका प्रयत्न हम साहित्यकार करेंगे, इस ध्येय को पूर्ण रूपेणसिद्ध करने में हम साहित्यकार अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देंगे। हम साहित्यकार मानते हैं कि नए साहित्य को देश की भुखमरी, राजनीतिक और सामाजिक दुर्दशा और गुलामी जैसे हमारे जीवन और मरण के प्रश्नों की विवेचना कर उससे निजात दिलाने की रास्ते की खोज करना चाहिए।"

उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का उर्दू के सभी साहित्यकारों ने दिल से स्वागत किया था और बहुत ही कम समय में, देश विभाजन के कगार पर खड़ा था तब ऐसे कठिन समय और परिस्थिति में भी 5 और 6 जुलाई 1947 को अहमदाबाद में उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ ने संगठन के राष्ट्रीय अधिवेशन और मुशायरे का आयोजन करने का निर्णय किया। यह ऐसा समय था जब देश के विभाजनकारी तत्व मुस्लिम लीग की सरपरस्ती में पाकिस्तान की मांग करते हुए प्रगतिशील शायर और अदीबों पर हमलावर थे। प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन और मुशायरे की घोषणा होते ही उसे निष्फल बनाने के लिए विरोधी तत्व मैदान में आ गए और अहमदाबाद से प्रकाशित साप्ताहिक इन्कलाब और मुस्लिम टाइम्स और डॉन में अधिवेशन और मुशायरे के बहिष्कार करने की अपील छपने लगी। इन अखबारों ने लिखा कि अधिवेशन और मुशायरे में कोई भी नामी शायर औ अदीब आने वाला नहीं है। इसीलिए आपको भी नहीं आना चाहिए। परन्तु अहमदाबाद के बाहर से आने वाले शायरों और अदीबो ने समय से पहुँचकर उनके दान्त खट्टे कर दिये थे।

5 जुलाई 1947 को अहमदाबाद के प्रेमाभाई हॉल में उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रथम सत्र प्रारम्भ हुआ। जिसकी अध्यक्षता कृष्ण चंदर ने की।

उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि "प्रगतिशील लेखक संघ उन बातों पर बहुत पहले विचार कर चुका है जिनका संबंध हमारी भाषा और साहित्य से है। लेकिन आज हमें उन बातो पर फिर से सोचना है क्योकि हालात पहले से कहीं अलग हैं। आज से 12 महीने पहले ऐसे हालात नहीं थे।"

जब कृष्ण चंदर ने अपना भाषण पूरा किया तो लोगों की तालियों से हॉल गूंज उठा। इसके बाद गुजरात के प्रगतिशील लेखक संघ के सचिव जनाब वारिस हुसैन अल्वी ने अपना स्वागत भाषण दिया जिसमें अधिवेशन के आयोजन की मुश्किलातों का वर्णन किया गया था। उसके बाद कैफी, मजरूह सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी तथा सरदार जाफरी ने अपनी अपनी प्रसिद्ध नज्में पढ़ी और अंत में जोश मलीहाबादी ने अपनी प्रसिद्द नज्म "जिन्दगी" पढ़ी जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया।

राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा सत्र 6 जुलाई 1947 को रात10 बजे प्रारम्भ हुआ जिसकी अध्यक्षता सज्जाद जहीर ने की, उन्होंने सर्वप्रथम प्रगतिशील लेखक संघ के उद्देश्य और अब तक की क्रियाकलाप के बारे में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की इसके बाद राष्ट्रीय शायरों के अतिरिक्त स्थानीय शायर जब्बर हुसेन 'अहमर' ने अपनी नज्म 'शायर और बरसात', तबस्सुम मुबराकपुरी ने अपनी नज्म, शायरे नौ 'वहीद बनारसी ने अपनी नज्म 'मेरी शायरी' और माइल भोपाली ने अपनी नज्म 'वादी– ए– कश्मीर' सुनाई जिसे लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय शायर कैफी आजमी, नियाज हैदर, साहिर लुधियानवी, मजाज लखनवी, मजरुह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी और जोश मलीहाबादी ने अपनी अपनी प्रसिद्ध नज्मे पढ़ी जिनको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके अतिरिक्त सरदार जाफरी ने अपना आलेख प्रस्तुत किया। इस तरह राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा सत्र भी अपने मुकाम पर पहुंचा।

1948 में भी कॉंफ्रेन्स और मुहासरे का आयोजन अहमदाबाद में जीपीओ के समीप स्थित सुतन अहमद यतीमखाने में उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में किया। जिसमें राजेन्द्र सिंह बेदी, कृष्ण चंदर, साहिर लुधियानवी, अली सरदार जाफरी, सागर निजामी, नियाज हैदर,और हबीब तनबीर के साथ बड़ी संख्या में

साहित्यकार और अदीब उपस्थित रहे थे। इस कार्यक्रम को गुजरात के तमाम अखबारो ने बड़े व्यापक ढंग से प्रकाशित किया था। इस कार्यक्रम से गुजरात की सियासी और अदबी दुनियां में भूकंप आ गया था और विरोधी तत्वों ने संगठन के ढीले ढाले लोगो को धमकाना शुरू कर दिया था और उन्हें इस्तीफा देने पर विवश कर दिया था।

1948 के मध्य में आजाद भारत की पहली सरकार ने प्रगतिशील लेखकों पर दमन करना प्रारम्भ कर दिया था। इतना ही नहीं अहमदाबाद के मजिस्ट्रेट ने उर्दू प्रगतिशील साप्ताहिक 'अदब–ए–लतीफ, और नकूश आदि पर अहमदाबाद में प्रतिबन्ध लगा दिया था। 18–19 सितम्बर को उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में अहमदाबाद के टाउन हॉल में इंकलाबी मुशायरे का आयोजन किया। परन्तु पुलिस द्वारा टाउन हॉल पर कब्जा कर लेने के कारण मुशायरा नहीं किया जा सका था और कुछ दिन बाद उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ के वहीद बनारसी, जमील कालीमी और अहसान जाफरी एवं जावेद अंसारी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर वडौदा जेल भेज दिया था।

29 अक्तूबर 1950 को वडौदा जेल में बंद सभी साहित्यिक कैदियों को छोड़ दिया गया गया था। परन्तु उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ को पुनः संगठित करने का कार्य 1951 में ही किया जा सका था, इस समय के दौरान कुछ लोगों ने किनारा कर लिया तो कुछ नये साहित्यकार उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े जिसमें मजरुल हक अल्वी, बदरुद्दीन, रशीद खान और रहमत अमरोही मुख्य थे। 1952 से 1959 तक उर्दू प्रगातिशील लेखक संघ द्वारा सम्मेलन और मुशायरे, शांति सम्मेलन और परिसंवादों का आयोजन किया जाता रहा।

24–25 अक्तूबर 1959 को उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ के तत्ववावधान में संगठन की कुल हिन्द कॉंफ्रेन्स (राष्ट्रीय कॉंफ्रेन्स) का आयोजन किया गया। कॉंफ्रेन्स का मुख्य ध्येय उर्दूभाषा के साथ हो रहे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना था। यह कॉंफ्रेन्स अभी तक की आयोजित कॉंफ्रेन्सों से भिन्न थी क्योकि इसके आयोजन में उर्दू शायर और अदीबो के अतिरिक्त गुजराती भाषा के लेखको और साहित्यकारों का सहयोग प्राप्त था। इस कॉंफ्रेन्स की स्वागत समिति के अध्यक्ष गुजरात के जाने माने बौद्धिक छोटुभाई नायक थे। कॉंफ्रेन्स का उद्घाटन गुजराती के मूर्धन्य साहित्यकार उमाशंकर जोशी ने किया था और महर्षि अरविन्द के भक्त हो जाने के बावजूद गुजराती के दुसरे साहित्यकार 'सुन्दरम ' ने दोनों दिन उपस्थित रहकर प्रगतिशील लेखन आन्दोलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की थी इसमें इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय स्तर के शायर कैफी आजमी, शकील बदायुनी, कैफ भोपाली, जाफर राही,और सफीक जौनपुरी उपस्थित थे।

गुजराती के मूर्धन्य साहित्यकार झबेरचंद मेघाणी की सर्वप्रथम राजकोट के शहर उपलेटा में प्रतिमा स्थापित करने उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ ने महती भूमिका अदा की थी।

अक्तूबर 1962 में कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार'आवामी दौर 'को मदद करने के लिए उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वावधान में मुशायरे का आयोजन किया गया था। तैयारियां चल रही थी कि उसी समय चीन ने हमला कर दिया।चीनी आक्रमण से देश में कार्यरत सभी वामपंथी आंदोलनों को धक्का लगा था। गुजरात का उर्दू प्रगतिशील लेखक संघ भी इससे बच नहीं सका। अंधराष्ट्रवादी ताकतों के चलते मुशायरा रोक देना पड़ा था इस घटना से तो उर्दु प्रगतिशील लेखक संघ की रीढ़ ही टूट गयी, आयोजकों खासकर तबस्सुम मुबारकपुरी व्यक्तिगत तौर से माली नुकशान उठा पड़ा था। इसी समय के दौरान इन्दिरागांधी ने कांग्रेस का विभाजन कर दिया था और उन्होंने जनता को लुभावने नारे तीये जिससे प्रभावित होकर उर्दू साहित्यकारो का एक बड़ा खेमा कांग्रेस से जुड़ गया था कांग्रेस में जाने वाले सक्रिय साथी थे जिससे उर्दू प्रगातिशील लेखक संघ छिन्न भिन्न हो गया था।

गुजरात में 70–80 के दशक में हिंदी के प्रगतिशील साहित्य का उद्भव हुआ। यों तो स्वामीनारायण सम्प्रदाय के अष्ट कवियों की हिंदी काव्य रचनाएँ और राजकुमारी सुजानबा और राजकुमार महिरामणसिंह की व्यथा कथा प्रवीणसागर के रूप में मिलती है। इसी तरह मीराबाई गुजरात में रहकर हिदी के भक्ति साहित्य में कुछ रचनाए की थी। लेकिन सही तौर पर सामाजिक और राजनीतिक चेतन से संपन्न हिंदी के साहित्यकार रामदरश मिश्र का अहमदाबद नौकरी करने आना, डॉ. महावीर सिंह चौहान का विविध शिक्षा संस्थानों में शिक्षा कार्य करना एवं मार्क्सवादी चेतना से लैस डॉ. शिवकुमार मिश्र का गुजरात में बस जाना ही गुजरात में प्रगतिशील हिंदी साहित्य के उद्भव का कारण माना जा सकता है, साथ ही साथ प्रगतिवादी साहित्यकार शमशेर बहादुर सिंह के सुरेंद्रनगर और अहमदाबाद में निवास करने से उसकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई। इसी के साथ क्रन्तिकारी समाजवादी (मा) लेनिनवादी) के महासचिव पंडित केशवप्रसाद शर्मा ने अहमदाबाद में हिंदी पढ़ने पढ़ाने वाले अध्यापकों और विद्यार्थियों (जिसमे कुछ साहित्यकार भी थे) को मार्क्सवाद लेनिनवाद से लैस करने का प्रयास किया जिससे प्रगतिशील हिंदी साहित्य के क्षेत्र में नए साहित्यकारों के लिए नयी जमीन तैयार हुई। जिसे सुलतान अहमद, फूलचंद गुप्ता, श्रीराम त्रिपाठी, जिलेदार सिंह डॉ. ईश्वरसिंह चौहान,डॉ. अख्तर खान पठान, करतार सिंह सिकरवार, घनश्याम मिश्र, रमेश मिश्र, सतपाल यादव आदि ने शामिल रहे। इसमें सुल्तान अहमद का हिंदी गजल और मार्क्सवादी आलोचना के क्षेत्र में बडा योगदान है।

जैसा पहले कहा जा चुका है, देश के आजाद होने और और इंदिरा गांधी के लुभावने नारों से प्रभावित होकर गुजराती और उर्दू के साहित्याकरों का एक बड़ा खेमा प्रगतिशील लेखक संघ को छोड़कर चला गया और जाने वालो में कुछ कर्मठ साथी भी थे। इस कारण गुजरात में प्रगतिशील लेखक आन्दोलन और प्रगतिशील लेखक संघ का कामकाज ठप्प सा पड गया था। लेकिन कभी कभी उर्दू और गुजराती के साहित्यकार अपने भूतकाल को याद कर खुशियाँ मना लेते थे। इसीलिए जब 1986 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्वर्ण जयंती मनाई गयी तब वह गुजरात में भी मनाई गयी थी और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित स्वर्ण जयंती महोत्सव में भाग लेने के लिए गुजरात से भी साहित्यकार गए थे।लेकिन संगठन के रूप में गुजरात में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रवृत्तियाँ बिलकुल ही बंद पड़ गयी थी।

परन्तु यहाँ पर एक बात अवश्य नोट किया जाना चाहिए कि प्रगतिशील लेखक संघ की प्रवृत्तियां बंद हो जाने बाद भी प्रगतिशील लेखन आन्दोलन जारी रहा और अनेकानेक प्रगतिशील साहित्यिक रचनाएँ भी रची गयी।जिनके कारण अनेक व्यक्ति और सहित्य समूह और संगठनो का उद्भव और विकास भी हुआ।

आजादी के पच्चीस साल के आसपास छात्रों में एक हताशा थी कि आजादी ने हमें बेरोजगारी और भूखमरी के अलावा और क्या दिया?

अहमदाबाद के कुछ कालेजों के युवा लेखकों ने 1972 में 26 जनवरी को भूखी जनवरी मनाकर भूख पर कविताएं और कहानियां लिखी और इनका प्रकाशन किया। इनमें मौन बलोली, बिपिन मेशिया और मनीषी जानी जैसे लेखक शामिल थे।

1975–76 में वामपंथी छात्र संगठनों के साथ जुड़े रहे दलपत चौहाण, प्रवीण गढवी और नीरव पटेल ने गुजराती दलित कविता का प्रारंभ किया।

1978 में अहमदाबाद में करोड़ों रुपए के खर्च के साथ होने वाले बाबा जयगुरूदेव के गायत्री यज्ञ के खिलाफ लोक अधिकार संघ, मजदूर संगठनों, दलित पैंथर और तर्कवादियों ने मिलकर बड़ा आंदोलन किया जिसमें मनीषी जानी लिखित नुक्कड़ नाटक कालोनियों, बस्तियों में एवं फैक्ट्रियों के दरवाजों पर बडे पैमाने पर खेला गया और गुजरात में पोलिटिकल नुक्कड़ नाटकों का प्राम्भ हुआ जिसमें हसमुख बाराडी, सरूप ध्रुव, हीरेन गांधी जैसे नाट्यकारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

1981 से नारीवादी आंदोलन के साथ साथ लेखन के कई स्वर उभरे जिसमें कुंदनिका कापड़िया, नीता रामैया, ईला आरब महेता, सोनल शुक्ल और सरुप ध्रुव प्रमुख रचनाकार रहे। क्रांतिकारी गाने एवं गरबा लिखने में सरुप ध्रुव का गुजराती साहित्य में विशिष्ट स्थान है।

1982 में क्रांतिकारी कवि हिम्मत खाटसूरिया की अगुवाई में संघर्ष साहित्य संघ की गुजरात में स्थापना हुई।

1990 में नुक्कड़ नाटकों का नेशनल फेस्टिवल गुजरात में हुआ। पंजाब, दिल्ली से लेकर केरल और आंध्र के रंगकर्मियों ने उसमें हिस्सा लिया।

1993 में लेखकों के हित, हक और गौरव के लिए काम करने वाले गुजराती लेखक मंडल के नाम से रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन शुरू हुई। जिसमें आज 1100 से ज्यादा लेखक जुड़े हुए हैं। यशवंत मेहता इसके पूर्व अध्यक्ष रहे, अभी प्रवीण गढवी अध्यक्ष हैं और मनीषी जानी प्रमुख हैं।

साहित्य की संघर्षशीलता को मद्देनजर रखते हुए उन्हें अपना आधार स्तम्भ मानता है।

जैसा पहले कहा जा चुका है कि गुजरात में प्रगतिशील लेखक संघ की प्रवृत्तियां नहीं थी उन्हें सक्रिय करने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे वर्ष 2005 प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक महासचिव सज्जाद जहीर की जन्मशताब्दी पूरे देश में मनाई जा रही थी गुजरात भी उसमें शामिल हो गया। उर्दू पाक्षिक 'हयात' के संपादक, वरिष्ठ पत्रकार और कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव शमीम फैजी के आग्रह पर गुजरात में सज्जाद जहीर शताब्दी मनाने का निर्णय लिया गया। इस सिलसिले में सज्जाद जहीर–जीवन और साहित्य विषय पर एक दिवसीय परिसंवाद का आयोजन अहमदबाद में किया गया जिसमें भाग लेने प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय महासचिव डॉ. कमला प्रसाद और उपमहासचिव डॉ. अली जावेद विशेष तौर पर अहमदाबाद आए। उनके मार्गदर्शन में परिसंवाद के अंत में पांच सदस्यों रामसागरसिंह परिहार, दिगंत ओझा, यशवंत मेहता, नटूभाई निम्बार्क और विजय ठाकुर की प्रगतिशील लेखक संघ की राज्य स्तरीय तदर्थ समिति का गठन किया गया। रामसागर सिंह परिहार को उसका संयोजक बनाया गया और प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य अधिवेशन बुलाने का निर्णय किया गया था।

उसी निर्णय को अमली जामा पहनाने के लिए 11 अप्रैल 2008 में अहमदाबाद में गुजरात भर के प्रगतिशील लेखक और साहित्यकारों के तत्वावधान में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रांतीय अधिवेशन हुआ जिसमें प्रलेस के राष्ट्रीय उपमहासचिव डॉ. अली जावेद उपस्थित रहे। अधिवेशन में खुले मन से साहित्यिक और सांगठनिक चर्चाएँ हुई। तब से लेकर आज तक गुजरात में प्रगतिशील लेखक संघ के नियमित प्रांतीय सम्मेलन होते हैं। हाल ही में विगत 25 जून को अहमदाबाद में प्रगतिशील लेखक संघ का 18वां प्रांतीय सम्मेलन हुआ जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ के राष्ट्रीय सचिव विनीत तिवारी केन्द्रीय पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित रहे, सम्मेलन ने मनीषी जानी, डॉ. सुल्तान अहमद, सरूप ध्रुव, मनहर जमील, दलपत चौहान,साहिर परमार का अध्यक्षमंडल, रामसागर सिंह परिहार को महसचिव और डॉ. ईश्वर सिंह चौहान को सचिव और सात सदस्यीय कार्यकारिणी का चयन किया और राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए 9 प्रतिनिधियों का भी चयन किया गया।

जहाँ तक प्रव्रत्तियों की बात है तो जब तदर्थ समिति थी तब और आज जब प्रांतीय समिति है तब गुजरात में प्रगतिशील लेखक संघ अनेकों परिसवाद, परिचर्चाओं का आयोजन कर चुका है। गुजराती साहित्यकार चन्द्र भाई भट्ट जन्मशताब्दी वर्ष, सुन्दरम एवं उमाशंकर जोशी का जन्मशताब्दी वर्ष, मखदूम मोहिउद्दीन, फैज अहमद फैज शताब्दी वर्ष, हिंदी के कवि त्रिलोचन,मुक्तिबोध और मंटो की जन्मशताब्दी के अवसर उनके साहित्य पर परिसंवादों का आयोजन किया गया। प्रगतिशील लेखक संघ ने गुजराती लेखक संघ में चल रहे गुजरात साहित्य अकादमी स्वायत्त आन्दोलन में प्रलेसं अपनी भूमिका अदाकर रहा है।

इसके अतिरिक्त अहमदाबाद में हर महीने के अंतिम शनिवार को सहित्यिक गोष्ठी का आयोजन होता है जिसमें नवोदित कवि, लेखक, साहित्यकार अपनी कहानी, कविता का पठन करते हैं उसके बाद उस पर सामूहिक विमर्श किया जाता है और जरुरत पड़ने पर मार्गदर्शन भी किया जाता है।

जैसे पहले बताया गया कि जब प्रगतिशील लेखक संघ की प्रवृत्तियां मृत प्राय थी तब गुजरात में अनेक तथा कथित मार्क्सवादी साहित्यिक समूह और संगठनो का उद्भव हो गया था, जो आज भी अपना अपना मंजीरा बजा रहे हैं। इसीलिए सांगठनिक तौर पर प्रलेस को विस्तृत करने में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी गुजरात में मिलनी चाहिए थी लेकिन कार्य तो जारी है।

बहाल होगा गंगा का निर्मल अविरल बहाव?

महेश राठी

मोदी सरकार को गंगा की सफाई पर फटकार के बाद गंगा की स्वच्छता, प्रदुषण रहित निर्मल अविरल प्रवाह फिर से चर्चाओं आया था। अपने अस्तित्व पर लगातार खतरे झेल रही भारत की इस जीवन रेखा को बचाने की मुहिम का विमर्श संभवतया अभी तक के अपने सबसे शीर्ष मुकाम पर होकर आ गया है। गंगा पुनरोद्धार पर एक अलग मंत्रालय बन जाने के बाद अब गंगा बचाने की मुहिम में कई प्रकार के दृष्टिकोण और उपायों की चर्चा पूरे भारतीय मीडिया के लिए एक उल्लेखनीय और ध्यानाकार्षक विषय बनता जा रहा है। विकास के नारे पर सवार हो सत्ता में आई सरकार के लिए विकास बनाम पर्यावरण एक अहम एवं विवादास्पद विषय है तो वहीं विकास और पर्यावरण के बीच समन्वय स्थापित करते हुए विकास का नया मॉडल अपनाना भी बहस का एक मुख्य विषय है, परन्तु इन विकल्पों से अधिक इस समय गंगा को प्रदूषित करने वाले कारकों और उनके स्तरों को समझाने की है।

दरअसल गंगा के अस्तित्व को खतरा पैदा करने वाले कारणों को हम तीन भागों में बांट सकते हैं, गंगा के उद्भव की अवस्था के मूल कारण, औद्योगिक विकासजनित कारण और जनसंख्या विस्फोट के कारण बढ़ता दबाव। गंगा को अपने उद्गम स्थल और पूरे उत्तराखण्ड में अभी तक भी एक स्वच्छ और निर्मल जलधारा के रूप में जाना जाता रहा है। यदि प्रत्यक्ष रूप से देखें तो गंगा की सभी सहयोगी जलधाराएं स्वच्छ और निर्मल दिखाई देती हैं परन्तु उत्तराखण्ड के किसी मूल निवासी से इसके बारे में जानने की कोशिश की जाए तो इस स्वच्छता की वास्तविकता और पिछले वर्षो में इसमें आई गिरावट को आसानी से समझा जा सकता है। वास्तव में यदि देखा जाए तो गंगा एक मैदानी नदी ही है क्योंकि गंगा देवप्रयाग में संगम के बाद ऋषिकेश में प्रकट होने के समय ही गंगा कहलाती है। इससे पहले गंगा अपनी सहयोगी जलधाराओं भागीरथी, मन्दाकिनी, पिण्डार, अलकनन्दा या मंदाकिनी आदि के नामों से ही जानी जाती है। परन्तु अपने बेसिन में संभवतया दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को आश्रय देने वाली आस्था और जीवन की प्रतीक इस नदी की यह सबसे बड़ी विडम्बना ही कही जाएगी कि यह महानदी गंगा बनने से पहले ही आज भारी प्रदूषण का शिकार हो रही है। गंगा का उद्गम स्थल ही हिमालयी राज्य उत्तराखण्ड विकास के नाम पर अवैध खनन और अतिक्रमण का शिकार होकर भारी पर्यावरण क्षति का शिकार हो रहा है और इसका दुष्प्रभाव लगातार घटते ग्लेशियरों और दरकते हुए पहाड़ों में साफतौर पर दिखाई देता है। जिस कारण गंगा और उसकी सहायक नदिया में लगातार पानी में कमी हो रही है पिछले पांच दशक में गंगा की समुद्र में पानी की हिस्सेदारी में बीस प्रतिशत से भी अधिक गिरावट आई है। पानी की इस कमी के लिए विकास के नाम पर उत्तराखण्ड में हो रहे अंधाधुंध बांध निर्माण की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस समय उत्तराखण्ड में तैयार हो चुके, निर्माणाधीन और छोटे बड़े प्रस्तावित बांधों की संख्या 300 से भी अधिक है। उत्तराखण्ड जैसे छोटे से पहाड़ी राज्य के लिए बेशक यह आंकड़ा हैरान कर देने वाला है। हालांकि अभी प्रस्तावित बांधों की बड़ी संख्या न्यायालय के हस्तक्षेप के कारण वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार कमेटी के पास विचाराधीन थी। फिर भी अभी तक बन चुके छोटे. बड़े अनेकों बांधों ने इस प्रदेश के समाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जीवन और परिस्थितिकी को बुरी तरह प्रभावित करके इस पूरे क्षेत्र पर निर्णायक अमिट छाप छोड़ दी है।

गंगा के प्रदूषण का दूसरा मुख्य स्रोत औद्योगिक इकाईयों द्वारा छोड़े जाना वाला औद्योगिक कूड़ा और शहरी मल है। गंगा नदी के किनारे कम से कम 29 बड़े शहर 70 कस्बे और हजारों गांव स्थित है जिनसे लगातार इस मल एवं अपव्यय का उत्सर्जन होता रहता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 तक गांव और शहरों के द्वारा छोड़े जाने वाले इस मल अपव्यय की की मात्रा 13 करोड़ लीटर रोजाना आंकी गई थी। इसके अलावा इस रिपोर्ट में औद्योगिक अपव्यय का अनुमान भी 260 मिलियन के आसपास किया गया था। गंगा के प्रदूषण में नगर निकायों की हिस्सेदारी सबसे बड़ी 80 प्रतिशत थी तो वहीं औद्योगिक इकाईयों की हिस्सेदारी 15 प्रतिशत ही मानी गई थी। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को आश्रय देने वाली इस महानदी के बेसिन में औद्योगिक इकाईयों की संख्या भी बेहद विशाल और बेतरतीब है। एक अनुमान के अनुसार ऋषिकेश से प्रयागराज तक विभिन्न प्रकार की 146 औद्योगिक इकाईयां विद्यमान थी जिसमें 144 उत्तर प्रदेश में और दो उत्तराखण्ड में स्थित थी। गंगा को बड़े स्तर पर प्रदूषित करने वाली इन इकाईयों में कानपुर में स्थित चमड़ा उद्योग का एक बड़ा योगदान रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले कई सालों में कई इकाईयों को बन्द करवाया या बन्द करवाने की प्रक्रिया शुरू की है। इसके अलावा इन औद्योगिक इकाईयों की सघनता को कनौज और वाराणसी के बीच में स्थित वैध, अवैध कारखानों और चर्मशोधन संयंत्रों की संख्या से ही समझा जा सकता है। इन औद्योगिक इकाईयों द्वारा पैदा किया जा रहा रासायनिक अपव्यय लगातार गंगा के पानी को प्रदूषित कर रहा है और इस बढ़ते प्रदूषण के कारण भारत की इस धार्मिक आस्थाओं की प्रतीक पौराणिक नदी का पानी न लोगों के पीने योग्य बचा है न ही स्नान करके पाप धोने लायक ही। इसके अतिरिक्त लगातार बढ़ती जनसंख्या का दबाव और लोगों की जीवनशैली में आ रहा परिवर्तन भी गंगा प्रदूषण को बढ़ा रहा है। बढ़ते शहरीकरण के कारण गंगा में गिरने वाले मल अपव्यय की मात्रा रोजाना बढ़ रही है। इस तेज होते शहरीकरण ने नदी तट पर होने वाले अतिक्रमण और नदी में से अवैध रेत खनन जैसे कारोबार को अराजक ढंग से बढ़ावा दिया है। इसके साथ ही भारतीय जीवन में गंगा नदी की धार्मिक महता भी गंगा के अस्तित्व के लिए संकट का कारण बन रही है। गंगा किनारे अन्तिम संस्कार इस दृष्टि से एक बड़ा संकट है जिससे गंगा के प्रदूषण में इजाफा होता है। यदि वाराणसी को इसका एक उदाहरण माने तो इस संकट को आसानी से समझा जा सकता है। वाराणसी में ही हर साल पचास हजार से अधिक शवों का अन्तिम संस्कार हो रहा है और गंगा का हर किनारा इस धार्मिक और सामाजिक विधान के लिए महत्वपूर्ण है। अब एक शहर के उदाहरण से शव दहन की इस प्रक्रिया की विशालता को समझा जा सकता है। यह कुछ ऐसे प्रमुख कारक हैं जो लगातार गंगा के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं।

भारत सरकार ने गंगा के निर्मल, स्वच्छ और निर्बाध प्रवाह को बनाए रखने के लिए 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में गंगा एक्शन प्लान की शुरूआत हुई। जिसमें 25 प्रथम श्रेणी शहरों में गंगा को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान चलाया गया बाद में 2000 में अधिकारिक रूप से दस गंगा एक्शन प्लान को बंद कर दिया परन्तु उससे पहले उस एक्शन प्लान के अनुभवों के आधार पर 1993 में एक्शन प्लान फेज 2 को अनुमति प्रदान की गई। इसके अलावा सरकार ने गंगा और उसके महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण सुरक्षा कानून 1986 के अन्तर्गत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी का 20 फरवरी 2009 को निर्माण किया गया। इस अथॉरिटी में संबंधित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी शामिल किया गया। इसी के साथ भारत सरकार ने गंगा को राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया। अब वर्तमान सरकार के सामने देश की जनता से किये गये विभिन्न वादो के अनुसार क्या बहाल होगा गंगा का निर्मल अविरल बहाव?

सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ एकजुट हो संघर्ष का आह्वान

जम्मू: अखिल भारतीय शांति और एकजुटता संगठन (एप्सो) ने देश की सभी शांतिप्रिय प्रगतिशील और लोकतांत्रिक ताकतों से एक साथ आने और उन सभी ताकतों के खिलाफ लड़ने का आह्वान किया है, जो चुनावी लाभ के लिए लोगों को सांप्रदायिक आधार पर लड़ाने पर आमादा हैं। यह आह्वान एप्सो के एक मंच से किया गया, जिसने विभिन्न समुदायों के बीच भाईचारे के बंधन को मजबूत करने का संदेश फैलाने के लिए यहां एक सभा का आयोजन किया था।

एप्सो के राज्य महासचिव राकेश शर्मा ने सभी प्रतिभागियों के स्वागत के साथ सत्र का आरंभ किया।

समारोह को संबोधित करते हुए एप्सो के महासचिव श्री हरचंद सिंह बाथ ने सभा को आश्वासन दिया कि भारत के लोग इस समय जम्मू–कश्मीर के लोगों के साथ एकजुट हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू–कश्मीर के लोगों का देशभक्ति का महान इतिहास है और उन्होंने जम्मू–कश्मीर की प्रगति और विकास तथा देश के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने मांग की कि भारत के संविधान की धारा 370 को तुरंत बहाल किया जाए और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। उन्होंने आगे कहा कि दुनिया के विकास और प्रगति के लिए शांति कायम रखना जरूरी है।

राज्य के एप्सो उपाध्यक्ष रोशन लाल मुदगिल रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध पर गंभीर चिंता जाहिर की और कहा कि इससे दुनिया पर उल्टा असर पड़ रहा है।

पूर्व राज्यसभा सदस्य अजीज पाशा ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तुरंत बहाल किया जाना चाहिए और जम्मू–कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए।

उन्होंने अपील की कि सभी लोकतांत्रिक और प्रगतिशील ताकतें भाजपा सरकार द्वारा अपनाई गई ध्रुवीकरण और विभाजन की नीतियों से लड़ने के लिए एकजुट होकर आगे आएं।

हाल ही में स्थिति का आकलन करने के लिए मणिपुर का दौरा करने वाली नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन (एनएफआईडब्ल्यू) की महासचिव एनी राजा ने कहा कि इस क्षेत्र में जो हुआ वह भारतीय इतिहास में एक काला अध्याय है और उन्होंने मांग की कि तुरंत शांति बहाल की जानी चाहिए।

उन्होंने कहा कि हत्या करने और लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

कार्यक्रम को संबोधित करने वाले अन्य लोगों में नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री अजय सधोत्रा, पूर्व राज्यसभा सदस्य शेख रहमान, वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमन भल्ला, सीपीआई (एम) के नेता हरि सिंह और अन्य शामिल थे।

बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर मणिपुर में जारी हिंसा की कड़ी निंदा की गयी, जहां निर्दोष महिलाओं पर हमला किया गया है। मीटिंग में मांग की गई कि मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और शांति बहाल करनी चाहिए। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए।

बैठक में हरियाणा सरकार के द्वारा एक विशेष समुदाय की संपत्तियों को नष्ट करने और सामूहिक दंड देने में तत्परता दिखाने के लिए भी निंदा की गई।

बैठक में वकीलों, शिक्षाविदों, नागरिक समाज के सदस्यों और अन्य सहित कई प्रतिष्ठित हस्तियों ने भाग लिया।

मीटिंग के समापन के अवसर पर जम्मू कश्मीर एप्सो के अध्यक्ष अश्विनी कुमार ने सभी का धन्यवाद किया।

नवउदारवाद एवं नव–फासीवाद भारतीय लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट

प्रताप नारायण सिंह

आज भारतीय लोकतंत्र के समक्ष कई समस्याएं गहराती नजर आ रही हैं। इससे देश के किसान, मजदूर, नौजवान एवं महिलाएं दुर्दशा का जीवन जीने को मजबूर हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया को फासीवाद से मुक्ति मिली थी। दुनिया के लोगों ने राहत की सांस ली थी। उसके बाद आजादी प्राप्त करने की ललक तमाम औपनिवेशिक देशों के क्रांतिकारियों के निरन्तर संघर्ष के फलस्वरूप सपने पूरे होने शुरू हो गए थे। भारत ने भी 1947 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद को सात समुन्दर पार वापस भेजकर ही दम लिया था। दुर्भाग्यवश जबसे भाजपा सरकार (2014) भारत की सत्ता में आयी है, तबसे पुनः नवउदारवादी नीतियों का सहारा लेकर नव फासीवाद का विस्तार करने में लगी है। हिटलर की तर्ज पर एक राष्ट्र, एक राजनीतिक पार्टी, एक भाषा, एक धर्म, एक फरमान की दिशा में लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। गोयबेल्स की तरह झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो के रास्ते पर चलकर आम जनता की समस्याओं को दरकिनार करते हुए पूरे देश में भाजपा का अखंड राज्य स्थापित करने के साथ–साथ सभी राज्यों में भी डबल ईजन की सरकार कायम करने की दिशा में कदम बढ़ाने के असफल प्रयास करने में जुटी है। इनका पहला नारा था देश नहीं बिकने दूंगा, कालाधन वापस लाकर देश के सभी गरीबों के खाते में 15–15 लाख जमा कर दिया जायेगा, दो करोड़ नौजवानों को हर वर्ष नौकरी दी जायेंगी। परंतु मोदी ने नोटबन्दी की अचानक घोषणा करके देशवासियों को संकट में फंसा दिया। पुनः 2023 में 2000 (दो हजार) के नोट को बंद करने की घोषणा करके फिर से लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में करके विपक्षी दलों के नेताओं को जेलों में बंद करके परेशान करने की नीति के साथ–साथ तमाम मीडिया को अपने अधीनस्थ कर नफरत की खेती का बड़े पैमाने पर प्रसार करके अपनी कमजोरियों को छिपाने की योजना पर मोदी सरकार चल रही है।

सरकार सड़क छाप गुंडों, बदमाशों के साथ पूंजीवाद एवं फासीवाद की तिकड़ी के माध्यम से जन असंतोष को दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जाति, धर्म, भाषा एवं नस्ल के आधार पर लगातार नफरत परोसी जा रही है। आरएसएस–भाजपा देश के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर ध्रुवीकरण की राजनीति को मजबूत करने में लगी है। मुसलमानों को तरह–तरह के आरोपों के माध्यम से उन्हें जेल के सीखचों में बंद किया जा रहा है। उन्हीं पर हमले होते हैं और उन्हीं पर मुकदमें कायम होते हैं और उनके घरों को बुलडोज किया जाता है। मजदूरों का लगातार शोषण जारी है। किसानों की आय दुगुना करने के बदले उन्हें तंगदस्ती का जीवन जीने को मजबूर किया जा रहा है। मजदूरों द्वारा उत्पादित उत्पाद के मूल्य में साझीदार न बनाकर उनके अतिरिक्त मूल्य का शोषण लगातार हो रहा है। बेरोजगारी चरम पर पहुंच चुकी है। पढ़े–लिखे नौजवानों को चैनलों के माध्यम से नफरत को आलिंगन करने का उपदेश दिया जा रहा है।

इस हमले से उबरने के लिए एक ही विकल्प है। देश के सभी विपक्षी राजानीतिक दलों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। अन्यथा भारतीय लोकतंत्र, भारतीय संविधान तथा साझी संस्कृति, साझी विरासत को नहीं बचाया जा सकता है। इसके लिए देश के सभी विपक्षी दलों को बिहार से प्रेरणा लेने की जरूरत है। बिहार में महागठबन्धन की सरकार ने भाजपा को अलग–थलग करने में सफलता पायी है। दूसरा कर्नाटक विधानसभा चुनाव में धार्मिक कार्ड बेअसर हो गया और भाजपा बुरी तरह धराशायी हो गयी। इसके लिए विपक्षी दलों को कुर्बानी देने की जरूरत है। देश के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती लोकतंत्र को बचाना, भारतीय संविधान को बचाना तथा संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल होने से बचाना तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना।

दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि उड़ीसा के बालासोर में ऐतिहासिक भीषण रेल दुर्घटना के फलस्वरूप रेलमंत्री घटनास्थल पर पहुंचकर वन्दे भारत का नारा लगाते हैं। मानवता शर्मसार हो गयी। सैकड़ों लोग काल के गाल में समा गए, बावजूद इसके किस खुशी में नारे लगाए गए। कितनी शर्म की बात है कि विगत वर्ष 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के लाल किले से बेटी पढ़ाओ–बेटी बचाओ की घोषणा करते हैं। वही दूसरी ओर उसी दिन बिलकिस बानों के साथ रेप करने वाले तथा उनकी बच्ची के साथ रेप कर उन्हें मारने वाले रेपिस्टों एवं अपराधियों को गुजरात सरकार आजीवन जेल की सजा काट रहे दरिन्दों को जेल से रिहाई करने का आदेश देकर उन्हें महिमामंडित करती है। इसी प्रकार जन्तर मंतर पर एक महीने से महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिह पर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए धरना दिया तो मोदी सरकार की दिल्ली पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करने के बजाये महिला पहलवानों को ठीक उसी खदेड़ खदेड़कर उन्हें जन्तर–मन्तर से हटाती है। यह उस दिन हुआ जिस दिन मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन कर रहे थे। देश की जनता को कोई भी चैनेल सही समाचार दिखाने से परहेज करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के द्वारा देश के किसानों ने, मजदूरों ने, नौजवानों ने तथा महिलाओं ने इस वीभत्स घटना को देखा। देशवासियों को अभी एक मात्र भरोसा उच्चतम न्यायालय पर टिका हुआ है। तानाशाही का एक अन्य उदाहरण राहुल गांधी के उपर मानहानि का मुकदमा है। राहुल गांधी का कसूर यह था कि उन्होंने लोकसभा के अंदर मोदी से पूछा कि आप और अदानी के बीच कैसा सम्बन्ध है। मोदी अदानी का साथ–साथ हवाई जहाज का फोटो भी सदन में दिखाया गया था। कहावत है खिसयानी बिल्ली खंभा नोचे। वही हुआ। मोदी सरकार ने पुराना मानहानि का केस गुजरात के अन्दर जो ठंडे बस्ते में था, उसे निकलवा कर कोर्ट में सुनवाई हुई और उन्हें दो साल कैद की सजा सुनाई गयी। इसके ठीक 24 घंटे के अन्दर मोदी सरकार ने उनकी संसद की सदस्यता रद्द करवाई और आनन फानन में उन्हें उनके फ्लैट से बाहर किया गया। जबकि अभी चार–पांच लोग संसद सदस्य नहीं रहते हुए भी वर्षो से भाजपा के नेता फ्लैट में शान शौकत से रह रहे हैं। यही नव–फासीवाद का संकेत है। ऐसी स्थिति में मध्यप्रदेश, राजस्थान एवं छत्तीसगढ़ में कुछ महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। ऐसी परिस्थिति में इन तीन राज्यों में विपक्षी दलों को दूध–पानी की तरह मुकम्मिल एकता कायम कर धार्मिक उन्मादों का जवाब संयम से देते ध्रुवीकरण को रोकने के प्रयास करने होंगे। यदि विपक्ष इसमें 2024 के लोकसभा चुनाव में सफल होता है तरे नवउदारवाद एवं नवफासीवाद के बढ़ते फन को कुचलने की तरफ कदम बढ़ाने में सफलता मिल सकती है। तभी भारतीय लोकतंत्र की रक्षा संभव है। सरकार धर्मनिरपेक्षता को दरकिनार करते हुए सांप्रदायिक राजनीति कर रही है। सरकार अपनी तरफ से हिन्दू भक्त होने का लगातार प्रदर्शन करती है। धर्म की राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष 2014 के बाद धार्मिक आयोजनों में सरकार की संलिप्तता में दिखता है। वर्तमान में सत्ता को बचाने के लिए सरकार ईडी, सीबीआई एवं इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करती दिख रही है जिसके लिए वह इन एजेसियों का दुरूपयोग करके विपक्षी नेताअें पर शिकंजा कसने का प्रयास कर रही है। इस प्रकार सरकार इन्हीं दो एजेंडो पर काम कर रही है। मोरवी से लेकर मणिपुर की घटनाओं के साथ–साथ उड़ीसा में हुए रेल हादसा में काल कवलित लोगों के लिए कफन कम पड़ गये हैं। इस प्रकार यह संकेत स्पष्ट मिल रहा है कि संविधान की शपथ लेकर सरकार देश में राजतंत्र लाना चाहती है। नई संसद में सेंगोल की स्थापना इसका प्रतीकात्मक प्रमाण है कि उनका कदम राजतंत्र की ओर बढ़ रहा है। मोदी सरकार देश में कानून और व्यवस्था को सुधारने के लिए संविधान की शपथ लेकर कारपारेट घराने को लाभ पहुंचाने में सक्रिय है। यह सरकार सार्वजनिक संस्थाओं को कारपोरेट घराने के हाथ धड़ल्ले से बेच रही है। किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए प्रतिपक्ष की उपस्थिति अनिवार्य है। भाजपा सरकार प्रतिपक्ष को ही समाप्त करने का षडयंत्र कर रही हैं। कबीर के ये पंक्ति प्रासंगिक है–

'कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक ।

बर्तन में ही भेद है, पानी सबमें एक ।। '

इस प्रकार कुंआ धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन सरकार रूपी बर्तन में ही भेद भरा हुआ है। अब देश की जनता भी समझ रही है। विपक्षी दलों की एकता भी बनती नजर आ रही है। घोषणा, दमन, उत्पीड़न एवं धार्मिक उन्माद आदि ने सभी को सरकार के खिलाफ एकजुट होने का अवसर दिया है । इतिहास साक्षी है–ऐसे संकट के समय मुकम्मिल विपक्ष की एकता कायम हुई है और सत्ता बदली है।

बिहार में 23 जून 2023 को 17 विपक्षी राजनीतिक दलों की बैठक पटना में आयोजित हुई। महज 36 घंटे पहले महाराष्ट्र के अन्दर उद्धव ठाकरे, पार्टी के नेता के घर पर ईडी का छापा पड़ना शुरू हो गया है। यह सिर्फ इसलिए कदम उठाया गया है जिससे विपक्षी दलों में दहशत फैल जाये। लेकिन ऐसे ढ़ेर सारे उदाहरण हैं जो डरने की बात दूर रही बल्कि पूरे हौसले के साथ सरकार के विरोध में खड़े हैं। फिर भी विपक्षी दलों को परेशान करने के लिए सरकार के तरकश में तीन ही तीर हैं। सीबीआई, ईडी एवं इनकम टैक्स। भाजपा के जयघोष में इन्हीं तीनों के नंगे नाच का सामना विपक्षी दलों के नेता कर रहे हैं। यह कोहरा जल्द ही हटने वाला है। सत्य परेशान तो होता है, लेकिन पराजित नहीं होता है। दशकों बाद फिर से बिहार अपना इतिहास दुहरायेगा। सुरसा की तरह भाजपा सरकार विपक्षी दलों के नेताओं पर दमन, उत्पीड़न का जाल संवैधानिक संस्थाओं द्वारा ज्यों–ज्यों बढ़ा रही है, उसी तरह विपक्षी राजनीतिक दलों की मुकम्मिल एकता उससे भी तीव्र गति से बढ़ती दिख रही है। तुलसी की ये पंक्तियां प्रासंगिक है–

ज्यों–ज्यों सुरसा बदन बढ़ावा।

तासु दुगुन कपि रूप दिखावा।।

अंत में– नौ वर्षो के अन्तराल में मोदी सरकार द्वारा जनता के बीच जुमलों के माध्यम से उन्हें जो भरोसा दिलाया गया था, अब वह भरोसा टूट रहा है। यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के मतदाताओं का स्वभाव काली मिट्टी की तरह होती है। जब भरोसे का पानी उसके उपर पड़ता है तो सत्ता के साथ इस तरह चिपक जाती है कि उसे छुड़ाने पर भी आसानी से अलग नहीं होती है। लेकिन जब भरोसा जुमला बन जाता है तो काली मिट्टी रूपी मतदाता के अन्दर का पानी सूख जाने पर उसका स्वभाव पत्थर जैसा हो जाता है। सूखी काली मिट्टी सर पर लगाने से लहुलुहान कर देती है। भारतीय लोकतंत्र का इतिहास रहा है कि 1967 में, 1977 में तथा 1989 में मतदाताओं ने सूखी काली मिट्टी बनकर तत्कालीन सत्ता को बेदखल करने में सफलता पायी थी। इसी प्रकार 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदाओं के अन्दर की नमी सूख चुकी है। पुनः पूर्व के इतिहास को दुहराने में अपनी अहम भूमिका का निर्वाह करेगी। आज देश के अन्दर कुशासन के खिलाफ न केवल देश के विपक्षी दलों की एकता मजबूत होती दिख रही है, बल्कि अब भाजपा नेताओं के अंदर भी मोदी महत्वकांक्षा के खिलाफ आवाज उठने लगी है। यह सत्ता परिवर्तन के लिए शुभ संकेत है। कवि कन्हैया की ये पंक्तियां प्रासंगिक है–

'इस हल्के नस्तर से काम नहीं चलेगा

जख्म बहुत गहरा है

केवल चिल्लाने से विघ्न नहीं टलेगा

आसमान बहरा है।'

हिन्दुस्तान की आजादी में रंगकर्मियों और संस्कृतिकर्मियों का योगदान

'इन्कलाब जिन्दाबाद, हिन्दुस्तान की आजादी जिन्दाबाद

जाहिद खान

देश की आजादी लाखों–लाख लोगों की कुर्बानियों का नतीजा है। जिसमें लेखक, कलाकारों और संस्कृतिकर्मियों ने भी अपनी बड़ी भूमिका निभाई। खासतौर से तरक्कीपसंद तहरीक से जुड़े लेखक, कलाकार मसलन सज्जाद जहीर, डॉ. रशीद जहां, मौलाना हसरत मोहानी, जोश मलीहाबादी, फैज अहमद फैज, फिराक गोरखपुरी, अली सरदार जाफरी, मजाज, मखदूम मोहिउद्दीन, कृश्न चंदर, ख्वाजा अहमद अब्बास, कैफी आजमी, मजरूह सुल्तानपुरी, इस्मत चुगताई, साहिर लुधियानवी, वामिक जौनपुरी, जांनिसार अख्तर, सैयद मुत्तलबी फरीदाबादी, यशपाल, बलराज साहनी, अण्णा भाऊ साठे, प्रेम धवन, डॉ. मुल्कराज आनंद, निरंजन सेन, रांगेय राघव, राजेन्द्र रघुवंशी, बिनय रॉय, शैलेन्द्र और एके हंगल आदि आजादी के आंदोलन में पेश–पेश रहे। अपने गीत, गजल, नज्म, नाटक, अफसानों और आलेखों के जरिए उन्होंने पूरे मुल्क में वतन–परस्ती का माहौल बनाया। गुलाम मुल्क में अपने अदब से उन्होंने आजादी के लिए जद्दोजहद की। अवाम में आजादी का अलख जगाया। अनिल डि सिल्वा, दीना गांधी, जोहरा सहगल, तृप्ति मित्रा, गुल बर्धन, दीना पाठक, शीला भाटिया, शांता गांधी, रेखा जैन, रेवा रॉय चौधरी, रूबी दत्त, दमयंती साहनी, ऊषा दत्त, कुदसिया जैदी, रशीद जहां, गौरी दत्त, प्रीति सरकार, नूर धवन जैसी महिलाओं ने भी इप्टा में मिली अलग–अलग भूमिकाओं को सफलतापूर्वक निभाया। अभिनय, गायन, नृत्य, निर्देशन से लेकर उन्होंने नाटक तक लिखे। इन अदीबों, कलाकारों और दानिश्वरों ने मुल्क की आजादी के लिए अपना सब कुछ झौंक दिया। अंग्रेजी हुकूमत के सैकड़ों जुल्म सहे, जेल में हजार यातनाएं सही। अपने परिवार से दूर रहे, लेकिन बगावत का झंडा नहीं छोड़ा। उनकी बेमिसाल कुर्बानियों के बाद ही आखिकरकार, मुल्क आजाद हुआ।

आजादी की पूर्व संध्या से लेकर पूरी रात भर देशवासियों ने आजादी का जश्न मनाया। बंबई की सड़कों पर भी हजारों लोग आजादी का स्वागत करने निकल आए। भारतीय जन नाट्य संघ यानी इप्टा के सेंट्रल स्क्वॉड ने इस खास मौके के लिए एक गीत रचा, जिसे गीतकार प्रेम धवन ने लिखा, पंडित रविशंकर ने इसकी धुन बनाई और मराठी के मशहूर लोकशाहीर अमर शेख ने इस गीत को अपनी आवाज दी। देशभक्ति भरे इस गीत के बोलों ने उस वक्त जैसे हर हिन्दुस्तानी के मन में एक नए आत्मविश्वास, स्वाभिमान और खुशी का जज्बा जगा दिया,''झूम–झूम के नाचो आज/गाओ खुशी के गीत/झूठ की आखिर हार हुई/सच की आखिर जीत/फिर आजाद पवन में अपना झंडा है लहराया/आज हिमाला फिर सर को ऊँचा कर के मुस्कराया/गंगा–जमुना के होंठों पे फिर है गीत खुशी के/इस धरती की दौलत अपनी इस अम्बर की छाया/झूम–झूम के नाचो आज।''

कैफी आजमी की शरीक–ए–हयात रंगकर्मी शौकत कैफी ने अपनी किताब 'याद की रहगुजर' में मुल्क की आजादी की पहली सुबह का क्या खूबसूरत मंजर बयां किया है, ''दिन गुजरते गए और हिन्दुस्तान की आजादी का हसीन दिन पन्द्रह अगस्त आ पहुँचा। कम्यून में सुबह–सवेरे से ही हलचल मच गई। तमाम कामरेड नहा–धोकर, जो भी अच्छे कपड़े थे, पहनकर तैयार हो गए और सवेरे आठ बजे ही कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर के सामने जमा होने लगे। तिरंगा लहराया गया। चारों तरफ नारों का शोर बुलन्द हो रहा था, ''इन्कलाब जिन्दाबाद, हिन्दुस्तान की आजादी जिन्दाबाद, भारत माता की जय, सल्तनते–बर्तानिया मुर्दाबाद।'' सबसे पहले मजाज ने अपना गीत सुनाया, 'बोल अरी ओ धरती बोल'। सरदार जाफरी ने एक इन्कलाबी नज्म पढ़ी। कैफी ने नज्म सुनाई। फिर पार्टी की खूबसूरत नौजवान लड़कियों ने जिनमें दीना और तरला भी थीं, 'सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्ताँ हमारा' गाया। पी. सी. जोशी और सज्जाद जहीर वगैरह ने तकरीरें भी कीं। फिर सब लोग जुलूस की शक्ल में जमा होने लगे। और मैं एक धान–पान–सी, दुबली–पतली लड़की आँखों में आजाद हिन्दुस्तान के वास्ते हसीन ख्वाब लिए कैफी का हाथ पकड़े–पकड़े उस जुलूस के साथ चल पड़ी। जुलूस ग्वालिया टैंक जाकर रुका। फिर तकरीरें, नाच–गाना, नारे और खूब हंगामे हुए। फिर जुलूस खत्म हुआ। मैं तो अपने कमरे में आकर सो गई। बहुत थक गई थी। लेकिन सरदार भाई, जोए अंसारी, मिर्जा अशफाक बेग, मेहँदी, मुनीष सब शहर में घूमते रहे। एक ईरानी होटल में गए, जहां जार्ज पंचम की बड़ी तस्वीर लगी थी। सरदार भाई मेज पर चढ़ गए और जार्ज पंचम की तस्वीर निकालकर जमीन पर पटक दी।''

प्रलेसं अधिवेशन में जाहिद खान की दो किताबों का विमोचन

प्रगतिशील लेखक संघ के इतिहास से रूबरू कराती किताबें

जबलपुर। प्रगतिशील लेखक संघ का 18वां राष्ट्रीय सम्मेलन 20, 21 और 22 अगस्त को जबलपुर में सम्पन्न हुआ। यह तीन दिवसीय सम्मेलन देश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई को समर्पित रहा। अनेक वैचारिक सत्रों में बंटे, इस अधिवेशन में वर्तमान के ज्वलंत मुद्दों के अलावा साहित्य और संस्कृति से जुड़े सवालों पर भी विस्तृत चर्चा हुई। जिसमें प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े देश भर के अलग–अलग भाषाओं के लेखकों ने बड़े पैमाने पर हिस्सेदारी की। अधिवेशन में वैचारिक सेशन के अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत जनगीत, लोकसंगीत, कला प्रदर्शनी, पोस्टर प्रदर्शनी, कार्टून प्रदर्शनी और नाटकों का प्रदर्शन भी हुआ। राष्ट्रीय अधिवेशन के तकरीबन हर सत्र में साहित्यिक लघु पत्रिकाओं के खास विशेषांकों और नई किताबों के विमोचन हुए। लेखक पत्रकार जाहिद खान की भी दो नई किताबों 'रूदाद–ए–अंजुमन' एवं 'तहरीक–ए–आजादी और तरक्कीपसंद शायर' का विमोचन हुआ।

'अंजुमन तरक्कीपसंद मुसन्निफीन' मुम्बई शाख के जलसों (साल 1946–47) की रूदाद (वृतांत) पर केंद्रित किताब 'रूदाद–ए–अंजुमन' का विमोचन वरिष्ठ आलोचक वीरेन्द्र यादव, इप्टा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नाटककार राकेश वेदा (उत्तर प्रदेश), लेखक स्वर्ण सिंह विर्क, प्रोफेसर हरभगवान चावला (हरियाणा), कवि–पत्रकार नथमल शर्मा (छत्तीसगढ़), कवि–नाटककार कुलदीप सिंह 'दीप' (पंजाब), कहानीकार जितेन्द्र विसरिया (मध्य प्रदेश) और प्रगतिशील लेखक संघ के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष पी. लक्ष्मीनारायण (आंध्र प्रदेश) ने किया। 'लोकमित्र प्रकाशन' से प्रकाशित लेखक पत्रकार हमीद अख्तर की किताब 'रूदाद–ए–अंजुमन' मूल रूप में उर्दू में लिखी गई है। जिसका शायर इशरत ग्वालियरी की मदद से जाहिद खान ने लिप्यंतरण किया है। इस साल उर्दू से हिन्दी लिप्यंतरण की यह उनकी दूसरी किताब है। इससे पहले मई महीने में रांची में आयोजित ऑल इंडिया उर्दू कन्वेंशन में अजीम अफसाना निगार कृश्न चन्दर के क्लासिक रिपोर्ताज 'पौदे' का विमोचन हुआ था।

जबलपुर अधिवेशन के दूसरे सत्र में जाहिद खान की दूसरी किताब 'तहरीक–ए–आजादी और तरक्कीपसंद शायर' का विमोचन महादेव टोप्पो, रणेन्द्र (झारखंड), अमिताभ चक्रबर्ती (पश्चिम बंगाल), डॉ. राहुल कौशाम्बी (महाराष्ट्र), डॉ. मोहनदास (केरल), डॉ. रबीन्द्रनाथ राय (बिहार), सुभाष मनसा (हरियाणा), वंदना चौबे (उत्तर प्रदेश), अर्जुमंद आरा (नई दिल्ली) और डॉ. ईश्वर सिंह दोस्त (छत्तीसगढ़) जैसे वरिष्ठ साहित्यकारों एवं चिंतकों ने किया। प्रलेस राष्ट्रीय अधिवेशन में लेखक जाहिद खान की दो किताबों का विमोचन किताब 'रूदाद–ए–अंजुमन' एवं 'तहरीक–ए–आजादी और तरक्कीपसंद शायर' पहुंचीं पाठकों के बीच।

रोडवेज कर्मचारियों ने प्रदेशभर में किये अर्धनग्न प्रदर्शन

जयपुर, 22 अगस्त 2023: राजस्थान रोडवेज के पांच श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे द्वारा रोडवेज बचाओ–रोजगार बचाओ संकल्प के साथ चलाये जा रहे आंदोलन के पांचवें चरण में मंगलवार, 22 अगस्त 2023 को दोपहर में प्रदेशभर में रोडवेज की सभी इकाइयों पर अर्धनग्न प्रदर्शन किये गये।

जयपुर में बड़ी संख्या में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा संयुक्त मोर्चे के घटक संगठनों के प्रमुख नेताओं की अगुवाई में अर्धनग्न होकर दोपहर एक बजे से दो बजे के मध्य सिंधी कैम्प बस स्टैंड के अंदर चारों ओर रैली निकालने के बाद मेट्रो स्टेशन के बराबर जुझारू अर्धनग्न प्रदर्शन किया गया।

संयुक्त मोर्चे के संयोजक एम. एल. यादव ने बताया कि गत विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस के जनघोषणा पत्र में रोडवेज एवं इसके कर्मचारियों को आर्थिक संकट से उबारने के लिये किये गये चुनावी वादा खिलाफी के विरोध एवं 11 सूत्री मांगों के लिये वर्तमान आंदोलन चल रहा है। रोडवेज प्रबंधन खुद भी औचित्यपूर्ण मांगों को पूरा करने के प्रति संवेदनशील नहीं है।

रोडवेज हित एवं कर्मचारी हित की मांगें स्वीकार नहीं होने की स्थिति में रोडवेज कर्मचारियों की 05 सितम्बर 2023 को प्रस्तावित प्रदेशव्यापी हड़ताल को रोकने के लिये राज्य सरकार द्वारा रेस्मा (काला कानून) का उपयोग करने की मीडिया खबर के सन्दर्भ में एम. एल. यादव ने कहा कि देश में लोकतंत्र की रक्षा की बात करने वाले राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरकार अगर नौकरशाही की सलाह पर रोडवेज कर्मचारियों के लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे रोडवेज बचाओ–रोजगार बचाओ आंदोलन से निपटने के लिये रेस्मा (काले कानून) का सहारा लेती है, तो यह उनके दोहरे चरित्र को उजागर करेगा।

संयुक्त मोर्चे के संयोजक ने कहा कि राज्य सरकार एवं रोडवेज प्रबंधन को खुले दिल–दिमाग से संयुक्त मोर्चे के साथ बातचीत करके मांगों को स्वीकार करने के लिये आगे आना चाहिये।

संदर्भः 30 अगस्त गीतकार शैलेन्द्र का जन्मदिवस और साल 2023 जन्मशती वर्ष

तू जिंदा है, तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर...

जाहिद खान

भारतीय जन नाट्य संघ (इप्टा) ने देश को कई शानदार कलाकार, गीतकार और निर्देशक दिए। शैलेन्द्र भी ऐसे ही एक गीतकार हैं, जिनकी पैदाइश इप्टा से हुई। इप्टा ने उन्हें नाम–शोहरत दी और इसके जरिए ही वे फिल्मी दुनिया तक पहुंचे। शैलेन्द्र एक क्रांतिकारी और संवेदनशील गीतकार थे। वे सही मायने में एक प्रगतिशील, जन कवि थे। उनकी कविताओं में सामाजिक चेतना और राजनीतिक जागरूकता साफ दिखलाई देती है। बाबा नागार्जुन, शैलेन्द्र को युग की व्यथा–कथा और जन मन के उल्लास का कवि मानते हैं। उनकी यह बात सही भी है। शैलेन्द्र की कोई भी कविता उठाकर देख लीजिए, उसमें सामाजिक यथार्थ के दृश्य बहुतायत में मिलते हैं। गीतों में तो फिर उनका कोई सानी नहीं था। गीतों में उनकी पक्षधरता स्पष्ट दिखलाई देती है और यह पक्षधरता है दलित, शोषित, पीड़ित, वंचितों के प्रति। उनके ज्यादातर गीत जिंदगी और जन आंदोलन से निकले हैं। वे खुद एक मजदूर थे और उन्होंने मजदूरों के दुःख–दर्द को करीब से जाना और देखा–भोगा था। जन आंदोलनों में शैलेन्द्र की गीतकार के तौर पर क्या अहमियत है, प्रसिद्ध आलोचक मैनेजर पाण्डेय इसे बयां करते हुए लिखते हैं,''जन आंदोलन से गीत के आत्मीय संबंध का बहुत अच्छा उदाहरण शंकर शैलेन्द्र के गीत हैं। शैलेन्द्र के गीत तेलंगाना आन्दोलन की देन हैं....आज हिन्दी में किसान जीवन के गीतकार अनेक हैं, लेकिन मजदूरों के संघर्ष और आन्दोलन का शैलेन्द्र से बेहतर गीतकार आज भी कोई दूसरा दिखाई नहीं देता।''

शैलेन्द्र का बचपन बेहद अभावमय और संघर्षों में गुजरा। स्कॉलरशिप और ट्यूशन पढ़ा–पढ़ाकर उन्होंने जैसे तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ–साथ उनका मन कविता में रमता था। जहां कहीं भी कवि सम्मेलन या मुशायरा होता, वे उसे सुनने जरूर जाते। कविताएं पढ़ते–सुनते, कब कविता उनके मिजाज का हिस्सा हो गई, उन्हें मालूम ही नहीं चला। वे खुद कविताएं लिखने लगे और वह दिन भी आया, जब कवि सम्मेलनों में उनकी भागीदारी श्रोता के तौर पर नहीं, बल्कि कवि के रूप में हुई। शैलेन्द्र ने अपनी वतनपरस्त और इंकलाबी कविताओं से जल्द ही एक अलग पहचान बना ली। वे अब कवि सम्मेलनों में कविता पढ़ने के लिए बुलाए जाने लगे। शैलेन्द्र की नौजवानी का यह दौर, वह दौर था जब देश में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। महात्मा गांधी के अहिंसक आंदोलन में कमोबेश देश की सारी जनता उनके साथ थी। स्वाभाविक ही है कि शैलेन्द्र पर भी इसका असर हुआ और उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इसके लिए वे जेल भी गए। कामगार यूनियन और इप्टा के सरगर्म मेम्बर के तौर पर उन्होंने मजदूरों की आवाज बुलंद की। उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया।

'प्रगतिशील लेखक संघ' और 'भारतीय जन नाट्य संघ' यानी इप्टा के मंचों से गाये गए शैलेन्द्र के गीतों ने तो उन्हें मजदूरों का लाड़ला गीतकार बना दिया। बंगाल के अकाल, तेलंगाना आंदोलन और भारत–पाक बंटवारे जैसे तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर उन्होंने कई माश्नी–खेज गीत लिखे। ''जलता है पंजाब साथियो....'' अपने इस गीत भावपूर्ण गीत के जरिए उन्होंने मुंबई की गलियों–गलियों से दंगा पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा किया। वामपंथी विचारधारा में डूबे उनके परिवर्तनकामी, क्रांतिकारी गीतों को सुनकर लोग आंदोलित हो उठते। उनके अंदर कुछ करने का जज्बा पैदा हो जाता था। इप्टा का थीम गीत ''तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर...'' शैलेन्द्र का ही लिखा हुआ है। ये ऐसा जोशीला गीत है जो आज भी जन आंदोलनों, नुक्कड़ नाटकों में कामगारों और कलाकारों द्वारा गाया जाता है। गीत का एक–एक अंतरा लोगों के दिल में कुछ करने का जज्बा पैदा करता है।

तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर
अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।

शैलेन्द्र मार्क्सवादी विचारकों और रूसी साहित्य से बेहद प्रभावित थे। इस साहित्य के अध्ययन से उनमें एक दृष्टि पैदा हुई, जो उनके गीतों में साफ नजर आती है। सर्वहारा वर्ग का दुःख, उनका अपना दुःख हो गया। इस दरमियान उन्होंने जो भी गीत लिखे, वे नारे बन गए। शैलेन्द्र का एक नहीं, कई ऐसे गीत हैं जो जन आंदोलनों में नारे की तरह इस्तेमाल होते हैं। मसलन ''हर जोर–जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है..', ''क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल !'', ''झूठे सपनों के छल से निकल, चलती सड़कों पर आ!'' इसमें भी ''हर जोर–जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है..'' मजदूर आंदोलनों का लोकप्रिय गीत है। मजदूर, कामगार इसे नारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह गीत जैसे उनमें एक जोश फूंक देता है। इस गीत को सुनकर मजदूर मर–मिटने को तैयार हो जाते हैं। गीत की घन–गरज ही है, कुछ ऐसी। यदि यकीन न हो, तो इस गीत के बोल पर नजर डालिये,

हर जोर–जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है
तुमने मांगें ठुकराई हैं, तुमने तोड़ा है हर वादा।

'न्यौता और चुनौती' शैलेन्द्र का एक अकेला कविता संग्रह है। जिसमें उनकी 32 कविताएं और जनगीत संकलित हैं। कविताएं साल 1945 से लेकर साल 1954 के बीच लिखी गई हैं। संग्रह की ज्यादातर कविताएं और गीत जन आंदोलनों के प्रभाव में लिखी गई हैं। इन गीतों में कोई बड़ा विषय और मुद्दा जरूर मिलेगा। 26 जनवरी, 1950 देश में नया संविधान बना और इस संविधान से सभी को समान अधिकार मिले। लेकिन यह संविधान भी देश के सभी नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाया। रोजी, रोटी और मकान जैसे बुनियादी अधिकारों को पाने के लिए जनता को सड़कों पर आना पड़ा। जो सत्ता में बैठा, अपने संवैधानिक कर्तव्य भूल गया। दमन उसका हथियार बन गया। शैलेन्द्र ने भारतीय लोकतंत्र की इन विसंगतियों का पर्दाफाश करते हुए लिखा,

मुझ जैसे ये लाखों हैं जो मांग रहे हैं
रोजी, रोटी, कपड़ा, बोनस औ, महंगाई
मांग रहे हैं जीने का अधिकार स्वदेशी सरकारों से!
किंतु सुना है, जीने का अधिकार मांगना
अब गुनाह है
गद्दारी है!
गद्दारी के लिए जेल, गोलीबारी है!
हुकमरान, सत्ता का किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं, शैलेन्द्र इन प्रवृतियों पर तंज करते हुए लिखते हैं,
''भगतसिंह ! इस बार न लेना काया भारतवासी की
देश भक्ति के लिए आज भी सजा मिलेगी फांसी की!

शैलेन्द्र ने यह गीत साल 1948 में लिखा था। इस गीत को लिखे सात दशक से ज्यादा हो गए, लेकिन सत्ता का किरदार नहीं बदला। सरकारें बदल गई, किरदार वही है। अंग्रेजों का बनाया देशद्रोह कानून आज भी सत्ताधारियों का प्रमुख हथियार बना हुआ है। जो कोई भी सरकारी नीतियों का विरोध करता है, उसे देशद्रोह कानून के अंतर्गत जेल में डाल दिया जाता है। शैलेन्द्र अपने गीतों में सिर्फ सरमायेदारी और साम्राज्यवाद का विरोध ही नहीं करते, बल्कि अपने गीतों में इसका एक विकल्प भी देते हैं। उनका मानना है कि समाजवाद में ही किसानों, मजदूरों और आम आदमियों के अधिकार सुरक्षित होंगे। उन्हें वास्तविक इंसाफ मिलेगा। लिहाजा वे इकट्ठा होकर सरमायेदारी के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ें। शैलेन्द्र की समाजवाद में

गहन आस्था थी। सोवियत रूस और चीन की साम्यवादी क्रांति के बारे में उन्होंने काफी कुछ पढ़ा था और उन्हें लगता था कि भारत में भी कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। देश का सर्वहारा वर्ग यदि एक हो जाए, तो परिस्थितियां बदलते देर नहीं लगेगी। यहां भी वास्तविक क्रांति हो जाएगी।

क्रांति के लिए उठे कदम
क्रांति के लिए जली मशाल!

शैलेन्द्र, को जिंदगानी का बड़ा तजुर्बा था और अपने इस तजुर्बे से ही उन्होंने कई नायाब गीत लिखे। सहज, सरल भाषा में अनोखी बात कह देने की उनमें एक कला थी। यही वजह है कि उनके गीत खूब लोकप्रिय हुए। शैलेन्द्र ने अपने संघर्षों से बहुत कुछ सीखा था। संघर्ष ही उनके गुरु थे। संघर्षों में ही तपकर वे कुंदन बने। साल 1949 में आई फिल्म 'बरसात' के दो गीतों ने शैलेन्द्र को रातों–रात देश भर में मकबूल बना दिया। कलाकार, निर्देशक राज कपूर और शैलेंद्र की जोड़ी ने आगे चलकर फिल्मी दुनिया में एक नया इतिहास रचा। उनकी जोड़ी ने एक साथ कई सुपर हिट फिल्में दीं। मसलन 'आवारा', 'अनाड़ी', 'बूट पॉलिश', 'श्री 420', 'जागते रहो', 'अब दिल्ली दूर नहीं', 'जिस देश में गंगा बहती है', 'संगम', 'मेरा नाम जोकर', 'चोरी–चोरी' और 'तीसरी कसम'। फिल्मों में मसरूफियत के चलते शैलेन्द्र अदबी काम ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो फिल्मी गीत हैं, उन्हें भी कमतर नहीं माना जा सकता। शैलेन्द्र के इन गीतों में भी काव्यात्मक भाषा और आम आदमी से जुड़े उनके सरोकार साफ दिखलाई देते हैं। अपने इन फिल्मी गीतों में उन्होंने किसी भी स्तर का समझौता नहीं किया।

गीतकार शैलेन्द्र के बारे में कहानीकार भीष्म साहनी का कहना था कि, ''शैलेन्द्र के आ जाने पर (फिल्मी दुनिया में) एक नई आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। यह आजादी के मिल जाने पर, भारत के नए शासकों को संबोधित करने वाली आवाज थी। इसके तेवर ही कुछ अलग थे। बड़ी बे बाक, चुनौती भरी आवाज थी। इसमें दृढ़ता थी। जुझारूपन था। पर साथ ही इसमें अपने देश और देश की जनता के प्रति अगाध प्रेमभाव था.....पर साथ ही साथ शासकों से दो टूक पूछा भी गया था,

लीडरो न गाओ गीत राम राज का
इस स्वराज का क्या हुआ किसान, कामगार राज का।

फिल्मों में शैलेन्द्र ने 800 से ज्यादा गीत लिखे, लेकिन इन गीतों में भी भाषा और विचारों की एक उत्कृष्टता है। अपने गीतों से उन्होंने हमेशा अवाम की सोच को परिष्कृत किया। वे जनता की नब्ज को पहचानने वाले गीतकार थे। फिल्मी दुनिया के अपने छोटे से करियर यानी सिर्फ सत्रह साल में शैलेन्द्र ने कई फिल्मों में सुपर हिट गीत दिए। साहित्यकार फणीश्वरनाथ रेणु की चर्चित कहानी 'तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम' पर शैलेन्द्र ने एक फिल्म 'तीसरी कसम' भी बनाई। कहानी की पटकथा खुद रेणु ने ही लिखी, जिसकी वजह से फिल्म काफी यथार्थवादी बन गई। उस दौर के लिहाज से ये शानदार फिल्म थी, जिसे बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन की तरफ से इस फिल्म को ग्यारह पुरस्कारों से नवाजा गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई। ख्वाजा अहमद अब्बास ने इसे सेल्यूलाइड पर लिखी कविता कहा। लेकिन व्यावसायिक तौर पर यह फिल्म नाकाम रही। 14 दिसम्बर, 1966 को महज 43 साल की उम्र में शैलेन्द्र ने यह दुनिया छोड़ दी। शैलेन्द्र को इस दुनिया से गए, एक लंबा अरसा बीत गया, लेकिन उनके गीतों की एक–एक पंक्ति अब भी फिजा में लहरा रही है और अवाम को प्रेरणा दे रही है,

तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर
अगर कहीं है स्वर्ग, तो उतार ला जमीन पर।

हिंसा मुक्त भारत: फासीवाद से संघर्ष की एक पहल

नई दिल्ली: देश के मौजूदा हालात में सत्ता के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बढ़त हुए फासीवादी हमलों ने देश की एकता और अखण्ड़ता को खतरे में डाल दिया है। ऐसे समय में विभिन्न सामाजिक संगठनों ने 19 अगस्त को नई दिल्ली के विट्ठल भाई पटेल भवन के डिप्टी स्पीकर हॉल में ''वायलेंस फ्री इंडिया'' विषय पर एक सभा का आयोजन किया। सभा हाल में लोगों की भारी संख्या में उपस्थिति लोगों में बढ़ती हिंसा को लेकर चिंता को रेखांकित कर रही थी।

इस सभा में बोलते हुए भाकपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व राज्यसभा सांसद अजीज पाशा ने इस बढ़ती हुई हिंसा को फासीवादी ताकतों विशेषकर आरएसएस–भाजपा की चुनावी तैयारी के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जाहिर करते हुए ईवीएम मशीन के चुनावों में इस्तेमाल पर सवाल उठाये। उन्होंने प्रिंसटन विश्वविद्यालय के कंप्यूटर वैज्ञानिकों के हवाले से बताया कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस ऐसा नहीं है जिसे हैक नहीं किया जा सके। उन्होंने प्रिंसटन के सेंटर फार इंर्फोमेशन एण्ड टेक्नोलॉजी विभाग के निदेशक का हवाले से कहा कि ई–वोटिंग मशीन और उसके नतीजों में गंभीर अनियमितताएं पायी गयी हैं। प्रिंसटन विश्वविद्यालय ने ईवीएम मशीन के प्रदर्शन के माध्यम से ही अपने तर्कों को सही ठहराया था। विश्वविद्यालय के इस प्रयोग के दस्तावेज ऑनलाइन भी उपलब्ध बताये जाते हैं।

इसके अलावा उन्होंने देश में एक समुदाय विशेष को लेकर चलाये जा रहे हिंसा के अभियान पर भी तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस के धार्मिक स्वतत्रंता आयोग ने भारत में बढ़ती हुई सांप्रदायिक हिंसा का संज्ञान लेते हुए इस पर 350 पेज से भी लंबा एक दस्तावेज हिंसक घटनाओं का हवाला देते जारी किया था। इसके अलावा भी पूरी दुनिया का मीड़िया मणिपुर से लेकर नूंह तक हुई शर्मनाक और भयावह हिसां पर रिर्पोटिंग कर रहा है और देश के प्रधानमंत्री को देश की बनती हुई इस शर्मनाक तस्वीर की कितनी फिक्र है यह इससे जाहिर हो जाता है कि जब मणिपुर जल रहा था तो उन्हें मणिपुर से ज्यादा अमेरिका यात्रा की फिक्र थी। इसके अलावा पडोस में नूंह पर उनकी खामोशी और संसद में अपने लंबे भाषण में मणिपुर पर केवल चन्द शब्द कहना उनकी संवेदहीनता और गैर जिम्मेदारी को दर्शाता है।

सभा को संबोधित करने वालों में राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा भी थे जिन्होंने आग लगाने के शौकीन एक राजा का हवाला देते हुए देश को चेतावनी दे डाली कि आने वाला चुनाव भारत के इतिहास में सबसे अधिक हिंसक चुनाव होने वाला है।

यूनाईटिड ओबीसी फोरम के नेता मुलायम सिंह यादव ने जहां अपलने भाषण में इंडिया नाम से बने विपक्षी गठबंधन का स्वागत किया तो इस पर एक सवाल भी उठाते हुए कहा कि क्या कोई भी गठबंधन दलितों को बाहर रखकर हो सकता है। उन्होंने कहा कि वैसे भी देश के इतिहास में सबसे अधिक हिंसा का समाना तो दलितों ने ही किया है। और यदि हिंसा को रोकने देश को बचाने के लिए कोई गठबंधन बन रहा है तो उससे दलितों को अलग नहीं किया जा सकता है। उन्होंने वहां मौजूद बसपा के नेता के माध्यम से बसपा सुप्रीमों मायावती से इस गठबंधन में शामिल होने की अपील भी की।

इसके हरियाणा के दलित, पिछडा, शोषित आवाज मंच के अध्यक्ष राजीव वर्मा ने भी सभा को संबोधित करते हुए बताया कि किस प्रकार हरियाणा के अंदर बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद आदि संगठन हिंसा की साजिशे कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सोनीपत में भी इन संगठनों ने ऐसे प्रयास किये परंतु उनकी और भाकपा की कोशिशों और भाकपा के राज्यसभा सांसद पी संदोषकुमार के प्रयासों से स्थिति को नियंत्रित किया गया।

इस सभा की अध्यक्षता ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिसे मुश्वरात के अध्यक्ष एडवोकेट फिरोज अहमद ने की और संचालन इसी संगठन के पूर्व अध्यक्ष नावेद हमीद ने किया। सभा को संबोधित करने वाले अन्य वक्ताओं में रालोद के चौ. यशवीर सिंह, बहुजन एकता मंच के के सी पिपल, वकील कोलिन गोंजालविस और बसपा के राज्य कोषाध्यक्ष सुरजीत सम्राट आदि शामिल थे।

भाकपा ने दी इसरो को बधाई

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी. राजा ने वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और वर्करों को और खासतौर से उस टीम को बधाई दी जिसने चंद्रयान–3 के चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग से भारत और भारतीयों को गौरवान्वित किया। डी. राजा ने ध्यान दिलाया कि हमारे देश के लिए सर्वश्रेष्ठ निवेश शिक्षा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है। मानवता के लाभ के लिए हमें उन्हें प्राथमिकता देनी चाहिए।

पी.पी.एच. पब्लिकेशन

पुस्तक	लेखक	मूल्य
1. भारतीय दर्शन में क्या जीवंत है और क्या मृत	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	500.00
2. बाल जीवनी माला	कॉपरर्निकस	12.00
3. बाल जीवनी माला	निराला	12.00
4. बाल जीवनी माला	रामानुज	12.00
5. बाल जीवनी माला	मेंडलिफ	50.00
6. बाल जीवनी माला	प्रेमचंद	50.00
7. बाल जीवनी माला	सी.वी. रमन	50.00
8. बाल जीवनी माला	आइजक न्यूटन	50.00
9. बाल जीवनी माला	लुईपाश्चर	50.00
10. बाल जीवनी माला	जगदीश चन्द्र बसु	50.00
11. फैज अहमद फैज–शख्स और शायर	शकील सिद्दीकी	80.00
12. फांसी के तख्ते से	जूलियस फ्यूचिक	100.00
13. कितने दोबाटिक सिंह भारत विभाजन की दस कहानियां	भूमिका: भीष्म साहनी	60.00
14. मार्क्सवाद क्या है?	एमिल बर्न्स	40.00
15. फैज़ अहमद फ़ैज़: प्रतिनिधि कविताएं	संप श्री अली जावेद	60.00
16. दर्शन की दरिद्रता	कार्ल मार्क्स	125.00
17. हिन्दू पहचान की खोज	डी.एन. झा	100.00
18. प्राचीन भारत में भौतिकवाद	देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय	200.00
19. 'जब मैंने जाति छिपायी थी' तथा अन्य कहानियां	बाबुराव बागुल	200.00
20. बाल–हृदय की गहराइयां माँ–बाप और शिक्षकों से अंतरंग बातचीत	वसीली सुखोम्लीन्स्की	350.00
21. चीन की पुरस्कृत कहानियां भाग–1, 2		185.00
22. बच्चों सुनो कहानी	लेव तोलस्तोय	175.00
23. जहां चाह वहां राह–उज़बेक लोक कथाएं		360.00
24. हीरेमोती–सोवियत भूमि की जातियों की लीक कथाएं		300.00
25. दास्तान–ए–नसरूदीन	लियोनिद सोलोवयेव	370.00
26. लेनिन–क्रुप्स्काया (संस्मरण)	क्रुप्स्काया	485.00
27. साम्राज्यवाद, पूंजीवाद की चरम अवस्था	लेनिन	65.00
28. बिसात–ए–रक्स	मख़दूम	100.00
29. भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण	भगवत शरण उपाध्याय	100.00
30. राहुल निबंधावली (साहित्य)	राहुल सांकृत्यायन	90.00
31. मैं नास्तिक क्यों हूं	भगत सिंह	75.00
32. विवेकानंद सामाजिक–राजनीतिक विचार	विनोय के. राय	75.00
33. रामराज्य और मार्क्सवाद	राहुल सांकृत्यायन	60.00
34. कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र	मार्क्स एंगेल्स	50.00
35. भगत सिंह की राह पर	ए.बी. बर्धन	15.00
36. माटी का लाल–कृति पुरूष कामरेड दुर्जन भाई	डा. रामचन्द्र	110.00
37. क्या करें	लेनिन	80.00
38. मेक इन इंडिया –आंखों में धूल	सी. मुरलीधर, एम. सत्यानन्द	30.00
39. भारतीय इतिहास में जाति और मुद्रा	इरफान हबीब	40.00
40. वर्ग जाति आरक्षण और जातिवाद के खिलाफ संघर्ष	ए.बी. बर्धन	60.00

आर्डर भेजें:
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड
5–ई, रानी झांसी मार्ग
नई दिल्ली–110055
दूरभाष: 011–23523349, 23529823
ईमेल: pph5e1947@gmail.com
https//pphbooks.net

दिल्ली के शोरूम
जी–18, आउटर सर्कल, कनाट प्लेस
नई दिल्ली–110001, फोन: 23324064
पीपीएच बुकशॉप, जेएनयू सेंट्रल लाइब्रेरी के पास,
नई दिल्ली–110 067, फोन: 65447645
पीपीएच शॉप, अजय भवन
15, कामरेड इन्द्रजीत गुप्त मार्ग, नई दिल्ली–2

नोट: आप भेज सकते हैं:
चेक, ड्राफ्ट या इलेक्ट्रानिक मनिआर्डर ''पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस (प्रा.) लिमिटेड'' के पक्ष में
बैंक विवरण:
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट: 32074674284, आई.एफ.सी. कोड: SBIN0009371

कुछ सामयिक मुद्दे एवं घटनाक्रम

पेज 5 से जारी...

सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज की पूर्व अध्यक्ष मृदुला मुखर्जी ने कहा कि ''यदि ''द वायर'' की रिपोर्ट सही है तो यह अत्यंत दुखद स्थिति है क्योंकि जो युवा स्कॉलर स्वतंत्र रिसर्च के काम में लगे हैं इसका उनके ऊपर अत्यंत डरावना असर पड़ेगा। इस प्रकार मेधावी युवा मस्तिष्कों को एकेडेमिक्स की तरफ हम कैसे आकर्षित कर सकेंगे?''

देश के 81 से अधिक संस्थानों के 288 अर्थशास्त्रियों ने प्रो. सब्यसाची दास के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है: ''हम, भारत में काम करने वाले अर्थशास्त्री दृढ़तापूर्वक विश्वास करते हैं कि एकेडेमिक स्वतंत्रता एक जीवंत शैक्षणिक एवं अनुसंधान समुदाय की आधारशिला है और हर व्यक्ति को ज्ञान पाने की कोशिश, अपने निष्कर्षों को आपस में बांटने और सेंसरशिप और प्रतिशोध के डर के बिना खुलकर संवाद करने का अधिकार है।''

उन्होंने अपने बयान में कहा है: ''हम सब्यसाची दास के साथ एकजुटता में खड़े हैं और अशोक विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग की मांगों का समर्थन करते हैं।'' उन्होंने अशोक विश्वविद्यालय की गर्वनिंग बॉडी से मांग की है कि प्रो. दास को तुरंत बहाल किया जाए।

बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के ए.जे.सी. बोस, इंडियन स्टेटिस्टिकल इन्स्टीच्यूट दिल्ली के अभिरूप भट्टाचार्य, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की अर्चना प्रसाद, आईआईएम बंगलुरू की अर्पिता चटर्जी और सेंट जेवियर विश्वविद्यालय कलकत्ता की देवलीना चक्रवर्ती आदि शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि अर्थशास्त्र विभाग के शिक्षक मांग कर रहे हैं कि प्रो. दास को वापस काम पर बुलाया जाए और गर्वनिंग बॉडी उनके रिसर्च पेपर के मूल्यांकन को बंद करे। उन्होंने एक खुले पत्र में मांग की है कि विश्वास दिलाया जाए कि ''फैकल्टी रिसर्च के मूल्यांकन में गर्वनिंग बॉडी की कोई भूमिका नहीं होगी।''

रोजगार में घट रही युवाओं की हिस्सेदारी

प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में भारत का एक युवा देश के तौर पर जिक्र किया जहां के युवाओं के सामने अनेक अवसर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि यह गर्व की बात है कि भारत में 30 वर्ष से कम की आबादी दुनिया में सबसे अधिक है।

अवश्य ही देश में युवाओं की बड़ी आबादी है परंतु इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि भारत के युवा जिस बेकद्री का शिकार हैं उसका दुनिया में अन्य कोई उदाहरण नहीं। भारत में 25 प्रतिशत से अधिक युवा बेरोजगार हैं।

युवाओं का बेरोजगार होना उनकी सबसे बड़ी बेकद्री है। उनके बीच बेरोजगारी का यह आलम है कि श्रम शक्ति में युवाओं की हिस्सेदारी ही घटती जा रही है।

सीएमआईई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनोमी) के रोजगार आंकड़ों के इंडियन एक्सप्रेस द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार मोदी सरकार के सात सालों की अवधि, 2016–17 से 2022–23 की अवधि में 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों की रोजगार में हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से 17 प्रतिशत से आ गई है। 30 से 44 आयु वर्ग के लोगों की भी रोजगार में हिस्सेदारी 38 प्रतिशत से घटकर 33 प्रतिशत पर आ गई, जबकि 45 वर्ष ऊपर के आयुवर्ग के लोगों की रोजगार में हिस्सेदारी 33 प्रतिशत से बढ़कर 49 प्रतिशत पर आ गई है। रोजगार में युवाओं की घटती हिस्सेदारी और 45 वर्ष से ऊपर के आयुवर्ग के लोगों की बढ़ती हिस्सेदारी रोजगार के मामले में भारत की स्थिति के बदतर होने की द्योतक है। मोदी सरकार की नीतियों में देश में रोजगार कम किया है और बेरोजगारी बढ़ाई।

2016–17 में 15 से 30 वर्ष के आयुवर्ग के युवाओं की भारत की श्रम शक्ति में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। मोदी सरकार की नीतियां रोजगार विरोधी रही हैं। उनकी रोजगार विरोधी नीतियों के फलस्वरूप श्रमशक्ति में युवाओं की हिस्सेदारी लगातार कम होती जा रही है।

2016–17 में 15 से 30 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं की भारत की श्रम शक्ति में 25 प्रतिशत हिस्सेदारी थी जो 2017–18 में घटकर 23 प्रतिशत, 2018–19 में 23 प्रतिशत, 2019–20 में 21 प्रतिशत, 2020–21 18 प्रतिशत, 2021–22 में 18 प्रतिशत और 2022–23 में 17 प्रतिशत पर आ गई।

2016–17 में रोजगार में लगे लोगों की कुल संख्या 41.27 करोड़ थी जो 2022–23 में घटकर 40.58 करोड़ रह गई। इसमें यह उल्लेखनीय है कि 2016–17 में 15 से 30 आयु वर्ग के लोगों की श्रमशक्ति में संख्या 10.34 करोड़ थी, जबकि 2022–23 में श्रमशक्ति में उनकी संख्या घटकर लगभग 7.1 करोड़ रह गई। इससे समझा जा सकता था है कि देश में बेरोजगारी कितनी भयानक है। ऐसे में प्रधानमंत्री का भारत की जनसांख्यिकी और भारत में युवाओं की दुनिया में सबसे बड़ी संख्या होने पर गर्व करना कोई मायने नहीं रखता। उन्हें युवाओं की इस दुर्दशा पर गर्व के बजाय शर्म आनी चाहिए।

क्या यह मोदी सरकार के लिए कलंक की बात नहीं है कि इस सरकार के सत्ता में आने के बाद युवाओं में रोजगार की दर साल–दर–साल घटती जा रही है? आबादी के किसी आयु समूह की रोजगार दर से पता चलता है कि उस आयु समूह की आबादी का कितना प्रतिशत हिस्सा रोजगार में लगा है। उदाहरण के लिए यदि 15 से 30 आयु वर्ग के लोगों की संख्या 100 है और उनमें से केवल 10 रोजगार पर लगे है तो उनकी रोजगार दर 10 प्रतिशत होगी।

2016–17 में 15 से 30 वर्ष की आबादी के लोगों के बीच रोजगार दर 29 प्रतिशत थी। मोदी सरकार के कार्यकाल में उनकी रोजगार दर बढ़ने के बजाय घटी है और घटते–घटते 2022–23 में 19 प्रतिशत पर आ गई।

2016–17 में 15 से 30 वर्ष की आबादी के लोगों के बीच 29 प्रतिशत की रोजगार दर थी जो 2017–18 में घटकर 27 प्रतिशत, 2018–19 में 25 प्रतिशत, 2019–20 में 24 प्रतिशत, 2020–21 में 19 प्रतिशत, 2021–22 में 19 प्रतिशत और 2022–23 में भी 19 प्रतिशत रही। (सभी आंकड़े द इंडियन एक्सप्रेस (23अगस्त 2023,पृ.9) के ''लेख यंग इंडियन्स, ऐजिंग वर्कफोर्स'' से उद्धृत)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत काम मांगने वालों की बढ़ती संख्या मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़ती बेरोजगारी की पुष्टि करती है। जिसे कहीं रोजगार नहीं मिलता वही मनरेगा के तहत काम करने जाता है। मनरेगा में काम मांगने वालों की बढ़ती संख्या इशारा करती है कि अर्थव्यवस्था ठीकठाक नहीं चल रही है। यदि अर्थव्यवस्था ठीकठाक चले तो उसमें रोजगार का सृजन होना चाहिए और फलस्वरूप मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्या घटनी चाहिए।

मनरेगा में काम मांगने वालों की संख्या आर्थिक वृद्धि से विपरीत समानुपाती होनी चाहिए अर्थात आर्थिक वृद्धि होगी तो मनरेगा में काम करने वालों की संख्या घटनी चाहिए और आर्थिक वृद्धि कम होगी तो मनरेगा में काम करने वालों की संख्या बढ़ेगी।

कृषि के बाद मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को रोजगार प्रदान करने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है। सीएमआईई और सीईडीए (सेन्टर फॉर इकोनोमिक डाटा एंड एनेलेसिस) के एक संयुक्त अध्ययन के अनुसार मोदी सरकार के कार्यकाल में 2016–17 से 2020–21 की अवधि में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में रोजगार लगभग 50 प्रतिशत कम हो गया है। 2016–17 में इस क्षेत्र में 5.1 करोड़ लोग काम करते थे जबकि 2020–21 में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 2.7 करोड़ रह गई। इससे बढ़ती बेरोजगारी का पता चलता है। नए रोजगार का सृजन नहीं हो रहा है और जो मौजूदा रोजगार है उसमें कमी आ गई।

सरकार और उसके प्रायोजित प्रचार के जरिये भारत की कैसी भी चमकीली तस्वीर पेश करने की कोशिश की जाए, देश के आर्थिक विकास के संबंध में कुछ भी दावे किए जाएं, बढ़ती बेरोजगारी इस तरह के तमाम प्रचार और दावों को खारिज करती है।

असहमति एवं विरोध को कुचले जाने का नोटिस ले रही है रेटिंग एजेंसियां भी

भले ही मोदी सरकार भारत को विदेशी निवेश के लिए एक आकर्षक स्थान बताने का कितना भी प्रचार करे परंतु वैश्विक रेटिंग एजेंसियां भारत को निवेश स्तर की सबसे निचली रेटिंग ''बीएए3'' पर ही रख रही हैं। वैश्विक रेटिंग एजेंसियां–फिच और एसएंडपी पहले ही भारत को ''बीएए3'' की रेटिंग दे चुकी हैं, रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी भारत को यही रेटिंग दी है। उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय वैश्विक रेटिंग एजेंसियों को लगातार प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है कि भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अतः वह एक सम्मानजनक निवेश ग्रेड क्रेडिट रेटिंग पाने का पात्र है। भारत सरकार लगातार लॉबिंग कर रही है कि भारत को बेहतर रेटिंग मिल जाए, परंतु रेटिंग एजेंसियां इस लॉबिंग के असर में नहीं आ रही हैं।

18 अगस्त 2023 को रेटिंग एजेंसी मूडीज ने स्थिर परिदृश्य के साथ भारत की साख बीएए3 को बरकरार रखते हुए कुछ जोखिमों का जिक्र किया। साख के बीएए3 होने को निवेश स्तर की सबसे निचली रेटिंग माना जाता है। आशंकाएं जताते हुए रेटिंग एजेंसी ने अपनी टिप्पणी में कहा, नागरिक समाज एवं राजनीतिक असहमति पर बंदिश के साथ संप्रदायों के बीच तनाव बढ़ने से राजनीतिक जोखिम और संस्थानों की गुणवत्ता के कमजोर आकलन को समर्थन मिलता है।

मूडीज ने कहा, हालांकि राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ने से सरकार के अस्थिर होने की आशंका नहीं है लेकिन घरेलू राजनीतिक तनाव बढ़ने से क्षेत्रीय एवं स्थानीय सरकारों के स्तर पर लोकलुभावन नीतियां अपनाने का जोखिम नजर आता है। गरीबी, आय–असमानता, साथ ही शिक्षा एवं बुनियादी सेवाओं तक असमान पहुंच जैसे सामाजिक जोखिम पहले से ही मौजूद हैं।

क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां स्थिर देशों, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास का दावा करते हैं, की रेटिंग का आकलन करते समय राजनीतिक जोखिमों के बजाय सामान्यतः आर्थिक मुद्दों पर फोकस करती हैं। अभी तक अपना क्रेडिट रेटिंग आकलन करते समय अधिकांश भूमंडलीय रेटिंग एजेंसियों ने भारत के वित्तीय घाटे, बढ़ती महंगाई और बढ़ते व्यापार असंतुलन के संबंध में चिंताएं व्यक्त की हैं। परंतु मूडीज ने ऐसे मुद्दों पर अपना फोकस शिफ्ट किया है जिन्हें मोदी सरकार या तो नजरन्दाज करती है या अन्य से छिपाती है या अपनी आलोचना को आक्रामक तरीके से कुचल देती है।

भारत की राजनीतिक जोखिमों का मूडीज द्वारा कटु आकलन उन विदेशी निवेशकों को एक स्पष्ट चेतावनी है जिन्हें अपने नाकाम हुए ''मेक इन इंडिया'' कार्यक्रम को पटरी पर वापस लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पटाने की बेतहाशा कोशिश कर रहे हैं।

मूडीज ने चेतावनी दी है कि ''राजनीतिक तनाव में वृद्धि और/ या चैक्स और बैलेनिस्ज के और अधिक कमजोर होने से भारत की दीर्घ–कालिक वृद्धि संभावनाएं कमजोर हो जाएंगी जो भारत की क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड करने में योगदान कर सकता है।

मणिपुर से चिंताजनक रिपोर्टें और वीडियो आना शुरू होने के बाद यह किसी वैश्विक एजेंसी द्वारा पहला क्रेडिट रेटिंग आकलन है। के

क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड कराने की भारत सरकार की कोशिशों के सिलसिले में अब से पहले मई 2023 में रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने कहा था कि वह उसकी क्रेडिट रेटिंग को उच्चतर करने पर विचार कर सकता है बशर्ते वह फिस्कल मीट्रिक्स (वित्तीय मापदंडों) को बेहतर बनाए और महंगाई को कम करे। परंतु उसने राजनीतिक जोखिमों और भारत में नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगाए जाने की चर्चा नहीं की थी।

मुक्ति संघर्ष

साप्ताहिक 27 अगस्त – 2 सितंबर, 2023

Delhi Postal Regd. No. DL(C)-01/1277/2021-23
Licenced to Post without Pre-payment. U(C)-102/2021-23
(R.N.I. No. 20196/70) Posted in LPC, DRMS, Friday & Saturday

प्रकाशन तिथि: 25.8.2023

भाजपा शासन में जनतंत्र पर खतरा

राम नरसिम्हा राव

वाइजेग, 17 अगस्त 2023: वाइजेग स्टील प्लांट के निजीकरण के खिलाफ वाइजेग स्टल प्लांट रक्षा समिति कैम्प के प्रचार अभियान की ''बस यात्रा'' का उद्घाटन, 17 अगस्त 2023 को वाइजेग के कुरमन्ना चेलम स्थिति वाइजेग स्टील प्लांट के बाहर, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सचिवमंडल सदस्य अमरजीत कौर ने किया। इस बस यात्रा का उद्घाटन करते हुए अमरजीत कौर ने कहा कि, ''भाजपा सरकार पूरे देश के लिए संकटपूर्ण हे। यह देश के लोगों को समझना होगा। जनता यहां सुरक्षित रहेगी बश्र्ते मोदी सत्ता से बाहर हैं। मोदी सरकार समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के विखंडन पर अमादा है। सार्वजनिक क्षेत्र के विखंडन और इस सरकार के खिलाफ संघर्ष देशभक्तिपूर्ण है। वाइजेग स्टील प्लांट का संघर्ष केवल स्टील प्लांट वर्कर्स का नहीं है वास्तव में यह संघर्ष सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को बेचे जाने के विरोध में देश के समस्त सार्वजनिक क्षेत्र के वर्करों का संघर्ष है।''

अमरजीत कौर ने अपने उद्घाटन भाषण में आगे कहा कि ''मोदी सरकार देश के लिए संकटपूर्ण है। जनतंत्र खतरे में है। राष्ट्र की संपत्ति और इसकी परिसंपत्तियों को कॉर्पोरेटों के हवाले किया जा रहा है जबकि देश की 80 करोड़ जनता गरीबी में जी रही है। स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा सुविधा जैसी अनिवार्य सुविधाएं आम जनता की पहुंच से बाहर हैं। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था के भगवाकरण के लिए पाठ्यक्रम में कई बदलाव किए हैं। चुनाव से पहले मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियों के सृजन का वायदा किया था और देश के हर नागरिक के खाते में 15 लाख रु. जमा करने का वादा भी किया था। इन वादों को पूरा किए बगैर मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कौड़ियों के भाव कॉर्पोरेट मालिकों के हवाले कर दिया है। अमरजीत कौर ने यह भी कहा कि मोदी की जन विरोधी नीतियों के कारण लोग पीड़ित हैं लेकिन मोदी आनंद कर रहे हैं। यह स्पष्ट सूचक है कि वह परपीड़क (सेडिस्ट) हैं। जिस तरह से सब्जियों और अनिवार्य वस्तुओं के दाम आकाश छू रहे हैं लोग उतना ही ज्यादा त्रस्त हैं। जिस तरह रोजगार की संभवानाएं घट रही हैं उससे देश की युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा पीड़ित है।

वर्कर्स के वेतन घटाए जा रहे हैं और अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। महिलाओं पर हमले और अत्याचार लगातार बढ़ रहे हैं कोविड महामारी के दौरान लाखों लोग बुहत बुरी तरह प्रभावित हुए। वे अपने गांव वापिस हजारों किमी पैदल चलने के बाद पहुंच पाए। लेकिन मोदी सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई।

मोदी ने मणिपुर दंगों पर तब तक मुंह नहीं खोला जब तक कि संसद में सवाल नहीं उठे। यहां तक कि मणिपुर का दौरा भी नहीं किया। स्वतंत्रता दिवस पर लालकिले से जो कुछ भी मोदी ने बोला वह कोरा झूठ है। 2024 के चुनावे मद्देनजर उनका भाषण चुनावी भाषण लग रहा था। मोदी ने स्वयं को भविष्य का प्रधानमंत्री घोषित कर दिया है। अमरजीत कौर ने सवाल उठाया कि जनतंत्र में कैसे कोई स्वयं के प्रधानमंत्री होने की घोषणा कर सकता है।

आंध्रप्रदेश भाकपा राज्य सचिव के रामकृष्णा ने अपने भाषण में कहा कि हाल ही में 26 पार्टियां मोदी सरकार के खिलाफ बंगलौर में इकट्ठी हुई थी और ये पार्टियां फिर से मुंबई में मिलेंगी। रामकृष्णा ने कहा कि आंध्रप्रदेश राज्य की कई मांगों जैसे कि, आंध्रप्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा, पोलावरम परियोजना का पूरा होना, उत्तरी आंध्रा का विकास, वाइजेग में रेलवे का निर्माण, कडापारे में स्टील प्लांट का पूरा होना बाकी है। उन्होंने कहा कि मोदी और जगन सरकार दोनों ने इन वादों को किया था।

अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रावुला वेंकैया ने अपने भाषण में कहा कि किसानों ने एक दीर्घकालीन जुझारू आंदोलन चलाया और वे अपने संघर्ष में कामयाब हुए इसी तरह वाइजेग स्टील प्लांट के वर्कर भी निजीकरण के खिलाफ अपने संघर्ष में सफल होंगे।

भाकपा राज्य सहायक सचिव मुप्पल्ला नागेश्वर राव ने अपने भाषण में कहा कि यदि विधानसभा में वाम दलों के विधायक होते तो वे राज्य के संसाधनों के दोहन को रोकते। आगामी चुनावों में लोगों को राज्य और केंद्र सरकार को हराना होगा।

भाकपा राज्य सहायक सचिव जे. बी. सत्यनारायण मूर्ति ने अपने भाषण में कहा कि मोदी का शासन केवल अंबानी और अडानी के लिए अच्छा है। गंगावरम बंदरगाह को अडानी को सौंप दिया गया है। गंगावरम के लोग एक बार स्टील प्लांट के कारण विस्थापित हुए थे और दूसरी बार फिर से बंदरगाह के निर्माण के कारण विस्थापित हो रहे हैं। सरकार ने मछली पकड़ने के दरवाजे बंद कर दिए है। जे.बी. सत्यनारायण मूर्ति ने चेतावनी देते हुए कहा कि वाइजेग की जनता खामोश नहीं बैठेगी यदि गंगावरम बंदरगाह वाइजेग स्टील प्लांट के कच्चे माल को रोकेगा।

भाकपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अक्कीनेनी वनजा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदिनारायन और एटक महासिचव जी. ओबुलेसु ने भी संबोधित किया। पैदीराजु भाकपा जिला सचिव ने अतिथियों का स्वागत किया। सीटू मंत्री अयोध्या राम, इंटक के राजेश्वर, एआईकेएस राज्य महासचिव के.वी.वी.प्रसाद, राज्य सचिवमंडल सदस्य पी. हरनाथ रेड्डी, ए.जी. स्टालिन, एनएफआईडब्ल्यू राज्य कार्यकारी अध्यक्ष, एआईवाईएफ, एआईएसएफ के राज्य नेता लेनिन बाबू जोनसन इप्टा राज्य महासचिव चन्द्रनायक, एटक जिला सचिव अच्युत राव भी बस यात्रा उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद थे।

इप्टा के जत्थे की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने आंदोलनकारी वर्कर्स के जोश को बुलंद रखा।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से डी. राजा द्वारा BFL Infotech Ltd. (Media Division), C-9, Sector-3, Noida, Dist. Gautam Budh Nagar, UP द्वारा मुद्रित, अजय भवन, 15–कामरेड इन्द्रजीत गुप्ता मार्ग, नई दिल्ली–110 002 से प्रकाशित। **संपादक**: रणबीर सिंह यादव फोन: 011–2323 0762 फैक्स 91–011–2323 5543.
e-mail: newagemukti@gmail.com, Layout: Udai Bhan Rajbhar.